सूर्योदय 6:39 सूर्यास्त 5:30

आज का तापमान

शिमला	11.0 न्यू	22.2 अधि
धर्मशाला	12.0 न्यू	25.5 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,219.65
निफ्टी	23,911.70

सोना 1,41,000 चांदी 1,84,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 5 नवंबर 2026 | 20 कार्तिक, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 190, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

मणिपुर में दो नगा उग्रवादी गुटों के बीच गोलीबारी, 4 की मौत

एजेंसी, नोनी। मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार सुबह करीब 4 बजे दो नगा उग्रवादी गुटों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 उग्रवादियों के मारे जाने की आशंका है। गोलीबारी में जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेंचुई) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के सदस्य के शामिल होने की आशंका है। यह घटना खौपुम इलाके के ताओदाइजांग गांव में हुई। घटना के बाद महिलाएं समेत कई गांव वाले मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों से गोलीबारी रोकने की अपील की। इस बीच, गोलीबारी के डर से गांव वाले अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।

अमूल का घी व बटर 50 रुपए तक महंगा



एजेंसी, नई दिल्ली। अमूल ने घी और बटर 3 से 50 रुपए तक महंगा कर दिया है। एक किलो घी का कार्टन 630 से बढ़कर 680 रुपए का हो गया है। बटर के 100 ग्राम पैक की कीमत 63 से बढ़कर 66 रुपए हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, दाम बढ़ने की वजह गुजरात-राजस्थान में नकली घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद ब्रांडेड घी की बढ़ी मांग है। इससे सितंबर 2025 की जीएसटी कटौती का फायदा भी काफी कम हो गया है। सितंबर 2025 में जीएसटी की दर घटने के बाद अमूल ने 700 डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम किए थे। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया था। उस समय एक लीटर घी के कार्टन की कीमत 650 से घटकर 610 रुपए हो गई थी। पांच लीटर का टिन 3,275 से घटकर 3,075 रुपए हो गया था। बटर के 100 ग्राम पैक की कीमत 62 से घटकर 58 रुपए हो गई थी। 500 ग्राम पैक 305 से घटकर 285 रुपए का हुआ था।

सीईसी ज्ञानेश कुमार पर 20 साल पुराने आरोप की होगी जांच

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होगी। केरलम के गृहमंत्री मेश चेन्निथला ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य में पीडब्ल्यूडी सचिव थे। कोल्लम के ठेकेदार साजन का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद पेमेंट करने के बदले 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस समय कांग्रेस की अगुवाई में पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने 140 में से 97 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने यहां 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है।

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप दोनों सदनों में हारे, डेमोक्रेट्स को बहुमत

अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बनेंगे अब्दुल अल-सैयद, ट्रंप ने कहा था 'जिहादी'

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं, मिशिगन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद ने जीत हासिल की। इसके साथ ही वह अमेरिकी इतिहास में सीनेटर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। ट्रंप ने अब्दुल को खुले मंच से 'जिहादी' कहा था। 25 अक्तूबर को मिशिगन में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रम्प ने कहा था, मैं यहां एक जिहादी और मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य को अमेरिकी सीनेटर बनने से रोकने आया हूं।

ट्रंप ने अब्दुल पर आतंकियों का साथ देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर अल-सैयद सीनेटर बनते हैं, तो उन्हें संसद में जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरना चाहिए। उन्होंने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए अल-सैयद की तुलना विमान हाईजैक करने वाले आतंकियों से भी की। हाउस में कुल 435 सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव हुए हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 231 सीटें, जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने 144 सीटें जीती हैं। सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 33 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 और रिपब्लिकन पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। बाकी 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों को मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 54 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हैं।

ईरान पर कार्रवाई का मौका मिला, तो अमेरिका के हित में लेंगे फैसला : ट्रंप



ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान पर दोबारा हमला करने का विकल्प खुला रखे हुए हैं। न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई का मौका मिला तो वे वही करेंगे, जो अमेरिका के हित में होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला करने का उनका फैसला सही था और वे आज भी इस पर कायम हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने 'पिकएक्स माउंटेन' पर हमले की संभावना भी जताई थी। मिडटर्म चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने ईरान पर दोबारा हमले की आशंका जताई थी।

चुनाव नतीजों से फर्क नहीं पड़ता दुश्मनी बनी रहेगी : खामेनेई



ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका मिडटर्म चुनाव के नतीजों से ईरान के साथ उसके रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आएगा। अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार आए या रिपब्लिकन की, ईरान के प्रति उसकी दुश्मनी बनी रहेगी। न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, खामेनेई ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने झुक जाए।

अग्निवीर अब 4 नहीं, 6 साल करेंगे नौकरी

3.18 लाख अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा; 25% पहले जैसे परमानेंट होंगे

एजेंसी, नई दिल्ली। अग्निवीर अब चार की बजाय छह साल तक सेना में नौकरी कर सकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को दो साल का सेवा विस्तार देने का ऐलान किया। इसका फायदा उन 75% अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्हें पहले चार साल बाद सेवा छोड़नी पड़ती थी।



अभी हर बैच के 25% अग्निवीरों को चार साल बाद मेरिट के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जाता है। बाकी 75% को सेवा से बाहर होना पड़ता है। नए नियम में 25% अग्निवीरों को नियमित करने का पुराना नियम जारी रहेगा। बाकी 75% को उनकी सहमति से दो साल और नौकरी करने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते भी मिलेंगे। छह साल बाद भी सेना में नौकरी करने के इच्छुक अग्निवीरों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

सेना को युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम : राजनाथ सिंह



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों के लिए दो साल के अतिरिक्त सेवा अवसर यानी 'सेकंड टू ऑफ ड्यूटी' को मंजूरी दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले से अग्निवीरों को शुरुआती सेवा अवधि के बाद भी सशस्त्र बलों से जुड़े रहने का अवसर मिलेगा। राजनाथ सिंह के मुताबिक, यह फैसला सेना में लंबे समय से किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सेना को युवा, फिट, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ भर्ती नीति नहीं है, बल्कि युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए भारतीय सेना को तैयार करने का रास्ता है।'

◆ दिसंबर तक 18,300 अग्निवीरों का कार्यकाल होना था पूरा

फिलहाल तीनों सेनाओं में करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं।

आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये पहले बैच में भर्ती हुए 24,400 अग्निवीरों का करीब 75% हैं। पहले तय योजना के मुताबिक नवंबर के मध्य से 75% अग्निवीरों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर किया जाना था।

नई व्यवस्था के तहत अब इन्हें दो साल का अतिरिक्त समय मिलेगा। यह सेवा विस्तार अग्निवीरों की सहमति से होगा। पिछले महीने एयरफोर्स ने अपने पहले अग्निवीर बैच के 2,850 रिक्रूट्स में से 712 को नियमित सेवा में बनाए रखने का फैसला किया था।

देश में 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनेंगी, बिजली स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ मंजूर

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें यौन शोषण-रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिजली स्टोर करने के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना स्वीकृत की गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 92 GWh ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना है, ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। इससे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सकेगा।



क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग को मंजूरी

वैष्णव ने कहा- कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की प्रोसेसिंग की योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद खदानों से निकाले गए या कच्चे खनिजों को इस तरह तैयार करना है कि उनका इस्तेमाल सीधे उत्पादन प्रक्रिया में किया जा सके।

सीएम ने अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

जीत उत्साह देती है, तो हार बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा : धामी

एजेंसी, गाजियाबाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गाजियाबाद में विद्या भारती द्वारा आयोजित 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया तथा सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के साथ ही उनमें अनुशासन, एकता, सहयोग और राष्ट्रभावना का विकास करती हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों की सहभागिता इस आयोजन को विशेष बनाती है। हिमालय के सीमांत क्षेत्रों से लेकर कन्याकुमारी और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर तक के खिलाड़ियों का एक मंच पर एकत्र होना लघु भारत का दर्शन कराता है।



मुख्यमंत्री ने अपने विद्यार्थी जीवन के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि विभिन्न भाषाओं, वेशभूषाओं और परिवेश से आए खिलाड़ियों को एक साथ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। खेल का मैदान सभी को एक सूत्र में जोड़ता है। यहां खिलाड़ी केवल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते, बल्कि एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में जीत और हार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जीत आगे बढ़ने का उत्साह देती है, जबकि हार अपनी कमियों को दूर कर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है।

दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव से रोकना गलत : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है।

इससे कम प्रजनन दर का मतलब है कि एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को पूरी तरह नहीं ले पाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन दर में गिरावट से बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है। इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को राहत दी। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण अयोग्य ठहराया गया था। बेंच ने 2003 के उस फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें दो बच्चों की शर्त को सही ठहराया गया था।



◆ कहा- कानून पर विचार की जरूरत; भारत में जन्म दर लगातार घट रही है

संगठन की असली पूंजी पुराने साथी : सैनी

भाजपा कार्यकर्ताओं से किया आत्मीय संवाद, पुराने साथियों को दिया सम्मान

एजेंसी, गुरुग्राम। किसी भी राजनीतिक संगठन की पहचान केवल उसके पदाधिकारियों और चुनावी सफलताओं से नहीं होती, बल्कि उन कार्यकर्ताओं से होती है, जिन्होंने दशकों तक विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन की नींव मजबूत करने में अपना जीवन लगा दिया।

समय के साथ जिम्मेदारियां और चेहरे बदलते हैं, लेकिन संगठन की सफलता में पुराने कार्यकर्ताओं का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को जब नेतृत्व स्वयं आगे बढ़कर सम्मान देता है, तो यह पहल महज औपचारिकता नहीं, बल्कि संगठन की कई पीढ़ियों को जोड़ने का माध्यम बन जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संवाद कर यही संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने जिस अपनत्व के साथ पुराने साथियों की बातें सुनीं और उनके योगदान को महत्व दिया, उससे कार्यकर्ताओं के चेहरों पर संतोष और भावुकता साफ दिखाई दी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संवाद कर उनका मन जीत लिया।

आज के नए कार्यकर्ता कल होंगे संगठन की धरोहर



वरिष्ठ भाजपा नेत्री व अधिवक्ता रश्मिभूषण ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मिला सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। आज जो कार्यकर्ता संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वे भी कल वरिष्ठ होंगे, जब वे देखेंगे कि पार्टी अपने पुराने साथियों के योगदान को याद रखती है तो उनका भरोसा और मजबूत होगा। उन्हें विश्वास रहेगा कि संगठन में समर्पण और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास संगठन के संघर्ष, विस्तार और बदलाव का लंबा अनुभव है। उनकी सक्रिय भागीदारी नई पीढ़ी को दिशा देने के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सकती है।

पंजाब के कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा

एजेंसी, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। बढ़ोतरी पहली नवंबर से लागू होगी और दिसंबर के वेतन व पेंशन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में सरकार बनने के समय महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। पिछले दो महीनों में महंगाई भत्ते में कुल 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

देश स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा आगे : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट और एक्सपो के सोलर प्लेनरी सत्र में दिल्ली की सोलर नीति, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा किए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के साथ कदमताल करते हुए राजधानी को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली सरकार इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली में तीन किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम मुफ्त लगाए जा रहे हैं, जबकि अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर 1.56 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली में अब तक लगभग एक लाख लोगों ने सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए पंजीकरण कराया है, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास और जागरूकता का प्रमाण है।

सौर ऊर्जा में देश के लिए मिसाल बनेगी राजधानी



मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का राजधानी की हर छत स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनाने और दिल्ली सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने का लक्ष्य है। भारत जिस गति से क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दिल्ली भी उसी कदमताल के साथ इस परिवर्तन का हिस्सा बनेगी। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के अनेक प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के लोगों का एक मंच पर आना स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

◆ दिल्ली में अब तक एक लाख लोगों ने सोलर ऊर्जा के लिए कराया पंजीकरण

राहुल गांधी का धुआं निकल चुका है : योगी

सीएम ने कहा- दोनों लड़कों की जोड़ी हारने के बाद बहाना ढूंढ़ती

एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर में बुधवार को भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा दोनों लड़कों की जोड़ी हारने के बाद बहाना ढूंढ़ती है। कभी ईवीएम तो कभी एसआईआर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कभी अपने नकारेपन को दोष नहीं देते। कांग्रेस राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च करेगी? राहुल का धुआं निकल चुका है। सीएम योगी ने कहा हार गए तो कमल दोषी, ईवीएम दोषी, लोकतंत्र पर खतरा नजर आने लगता है, अगर ईवीएम इतनी ही गलत थी तो उसी ईवीएम से जीतकर राहुल गांधी संसद में शपथ क्यों लेते हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माइक संभालते ही भोजपुरी में लोगों का हालचाल पूछा। उन्होंने कहा- रउवा सब ठीक बानी ना? नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा मुख्यमंत्री जी, राहुल की लॉन्चिंग की बात कर रहे थे। केवल उनका रॉकेट ही खराब नहीं है, बल्कि उनका लॉन्चिंग पैड भी खराब है, जिसने उनको पैदा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी भीड़ का 10 प्रतिशत भी विपक्ष रामलीला मैदान में नहीं जुटा पाया। विपक्ष देश को भरमाने का काम कर रहा है। रैली में 12 जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 'मोदी है-मोदी रहेगा' लिखी तख्तियां हाथों में लेकर रैली में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह देश के लोकतंत्र को बचाने, अराजकता को उखाड़ फेंकने और देश के खिलाफ हो रही साजिशों को बेनकाब करने के लिए है। विपक्ष के लोग हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं।

देश को बांग्लादेश बनाने वाले सुन लें यह नया भारत



सीएम ने कहा जो लोग देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, फ्रांस बनाना चाहते हैं, वे जान लें कि यह नया भारत है, यह नया भारत अपने महापुरुषों का सम्मान करता है, लेकिन अराजकता को स्वीकार नहीं करता है। आतंकवाद को बर्बाद करता है। नक्सलवाद को जहां जाना था, वहां पहुंचा दिया गया है। उन्होंने इस दौरान कहा- सभी लोगों दोनों हाथ उठाकर बोलें- लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ।

संबोधन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा- चुराह के चार सरकारी स्कूल बनेंगे सीबीएसई से संबद्ध

राजस्थान को बिजली बेचकर 4 माह में 400 करोड़ कमाएगा हिमाचल

भारतेन्दु संवाददाता, चंबा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रही है। इसी दिशा में राजस्थान को 15.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने का समझौता किया गया है।

इससे आगामी चार महीनों में प्रदेश को लगभग 400 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू कला मंच में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरी, थल्ली, जज्जाकोठी और मारूंड को सीबीएसई से संबद्ध करने की घोषणा की।



इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचायतों में सड़क निर्माण के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूरे होने के बाद प्रदेश सरकार इसमें नि:शुल्क बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करवाने के लिए प्रयासरत है। वहीं, वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला मामले में कानूनी लड़ाई जीतने से प्रदेश को 401 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब ई-नीलामी के माध्यम से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 37 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों और पशुपालकों को बेहतर समर्थन मूल्य दे रही है। कच्ची हल्दी 150 रुपए, गेहूं 80 रुपए और मक्की 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है। वहीं गाय के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए और भैंस के दूध का 71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में 100 से अधिक नए सीबीएसई विद्यालय खोलने की योजना है तथा 2,700 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में हिमाचल वर्ष 2025 में देश में पांचवें स्थान पर पहुंचा है, जबकि वर्ष 2021 में प्रदेश 21वें स्थान पर था।

मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना अगले माह होगी शुरू

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले माह से मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस योजना से चुराह क्षेत्र की लगभग 15 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों और केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बावजूद प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से विकास कार्यों को गति दे रही है। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना, विधायक नीरज नैय्यर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज, जिला परिषद अध्यक्ष रेखा ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कर्मचारियों-पेंशनरों की दिवाली होगी खुशहाल

आर्थिक चुनौतियों के बीच कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दीपावली के त्योहार को देखते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि दीपावली से पहले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन और मासिक भुगतान उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि त्योहार के अवसर पर किसी भी कर्मचारी की दिवाली फीकी नहीं रहनी चाहिए। चाहे कर्मचारी नियमित हो या अस्थायी, सभी को समय पर भुगतान मिलना चाहिए। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.50 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न होने देने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिले, ताकि वे अपने परिवार के साथ दीपावली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मना सकें। त्योहारी सीजन में बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ ही घरेलू खर्च भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों को अपनी जरूरतों और त्योहार की तैयारियों के लिए आर्थिक सहूलियत मिलेगी।

प्रदेश में दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने की परंपरा रही है। सरकार ने मौजूदा वित्तीय चुनौतियों के बावजूद इस परंपरा को कायम रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निचले पायदान पर कार्यरत कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है। सरकार का मानना है कि नियमित कर्मचारियों के साथ अस्थायी और अन्य श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी समय पर भुगतान मिलना जरूरी है, ताकि किसी को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकार के इस निर्णय से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। करीब 3.50 लाख लाभार्थियों के खातों में समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिवाली से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के हितों और त्योहार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार के इस कदम को त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। समय पर वेतन और पेंशन मिलने से कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को दीपावली की तैयारियां करने में सहूलियत मिलेगी। प्रदेश में दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने की परंपरा रही है। सरकार ने मौजूदा वित्तीय चुनौतियों के बावजूद इस परंपरा को कायम रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निचले पायदान पर कार्यरत कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है।

भारत-नेपाल ऊर्जा सहयोग को मिलेगी नई गति लोअर अरुण परियोजना के प्रमुख कार्य आरंभ

अरुण-3 और लोअर अरुण परियोजनाएं भारत-नेपाल ऊर्जा सहयोग का आधार



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से एसजेवीएन के शीर्ष प्रबंधन ने पूर्वी नेपाल में संचालित अपनी प्रमुख परियोजनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। काठमांडू में नेपाल सरकार के साथ उच्चस्तरीय आधिकारिक विचार-विमर्श के बाद एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना स्थलों का दौरा कर निर्माण कार्यों, तकनीकी तैयारियों और प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान निदेशक (वित्त) पार्थजीत डे और निदेशक (परियोजनाएं) राजेश कुमार चंदेल भी मौजूद रहे।

दौरे के दौरान प्रबंधन ने 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण-3 जलविद्युत परियोजना के बांध स्थल और विद्युत गृह स्थल सहित विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर चल रहे कार्यों की स्थिति, तकनीकी मानकों और परियोजना के अगले चरणों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण की प्रगति और कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों की जानकारी भी प्राप्त की।

इसके बाद एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने 669 मेगावाट क्षमता वाली लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के स्थल का दौरा किया। यहां नवंबर 2026 से लक्षित निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे, संसाधनों और निर्माण संबंधी व्यवस्थाओं को समय रहते सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

कर्मचारियों और निर्माण एजेंसियों को दिए निर्देश

एसजेवीएन के सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता ने परियोजना स्थलों पर तैनात एसजेवीएन, एसएपीडीसी और एसएलपीडीसी की टीमों को संबोधित किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद कार्य कर रहे इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन रणनीतिक परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

अरुण परियोजनाओं से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा

एसजेवीएन प्रबंधन ने दोहराया कि अरुण-3 और लोअर अरुण परियोजनाएं भारत और नेपाल के बीच स्वच्छ ऊर्जा सहयोग की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने के साथ सतत बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने दोनों परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

शिमला में पटाखों की बिक्री के लिए 14 स्थान तय

शिमला में 4 से 9 नवंबर तक पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। दिवाली पर्व के दौरान आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने शिमला नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल के लिए 14 स्थान निर्धारित किए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 4 से 9 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इसके तहत पटाखों की बिक्री, उपयोग, परिवहन और भंडारण को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि दिवाली के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदारों और लोगों द्वारा पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल किया जाता है। इससे आगजनी, विस्फोट और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसी घटनाओं में जान-माल का नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसुरक्षा के लिए बिक्री स्थल निर्धारित किए गए हैं।

इनमें आइस स्केटिंग रिंक, पुराना एसपीएम ग्राउंड इंजन घर संजौली, बालूगंज ग्राउंड, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल, खलीणी बाईपास, छोटा शिमला-कसुम्पटी मार्ग, फागली, पुलिस मुख्यालय निगम विहार, भट्टाकुफर पंचायत ग्राउंड, कंगनाधार बस स्टैंड, विकास नगर पुलिस चौकी, रानी ग्राउंड कसुम्पटी, न्यू पार्किंग टूटू और संकटमोचन मंदिर की कार पार्किंग की ऊपरी मंजिल शामिल हैं।

डॉ. शिव कुमार मेमोरियल जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य समापन



भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। स्पेशल ओलंपिक भारत, कांगड़ा चैप्टर के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय डॉ. शिव कुमार मेमोरियल जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का बुधवार को शिव सेवा सदन स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, सलियाना में समापन हुआ। समारोह में एसडीएम पालमपुर डॉ. ओपी यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कोड स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, सिद्धपुर ने ऑलराउंडर ट्रॉफी अपने नाम की।

◆ सिद्धपुर के कोड स्कूल ने जीती जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की ऑलराउंडर ट्रॉफी

मुख्य अतिथि ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन, टीम भावना और आत्मनिर्भरता विकसित करने का भी महत्वपूर्ण जरिया हैं। उन्होंने प्रतिभागियों की मेहनत और खेल भावना की सराहना की। आयोजन में पालमपुर रोटरी हेल्पेज फाउंडेशन और रोटरी आई फाउंडेशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्पेशल ओलंपिक भारत, कांगड़ा चैप्टर के सचिव बलबीर गुलेरिया तथा नेशनल कोच अमन कुमार और सुरेश कुमार ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विशेष बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करने के साथ खेलों के प्रति रुचि, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना था। इसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

राजकीय सम्मान के साथ देओठी में पंचतत्व में विलीन हुए नंद लाल

मुख्यमंत्री सुक्खू ने नंद लाल को नम आंखों से दी अंतिम विदाई

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला



सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे नंद लाल का बुधवार को उनके पैतृक गांव देओठी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने देओठी पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने नंद लाल के योगदान को याद करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही और सरल, विनम्र एवं मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने रामपुर क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया। विधानसभा में वह हमेशा गरिमा, मर्यादा और तार्किक ढंग से अपनी बात रखते थे। जनहित के मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और संसदीय परंपराओं की समझ उल्लेखनीय थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंद लाल के निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और समर्पित जनसेवक खो दिया है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान की कमी हमेशा महसूस होगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक कुलदीप सिंह राठौर और हरीश जनारथा सहित प्रशासनिक अधिकारी, आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर में चमके भरवाईं के स्वयंसेवी

◆ राज्य स्तरीय शिविर में रिद्धिमा का चयन, दिव्यांश को मेहनत की सीख



भारतेन्दु संवाददाता, भरवाईं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवाईं के दो राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवियों ने राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया। शिविर में विद्यालय की ओर से छात्र वर्ग में दिव्यांश और छात्रा वर्ग में रिद्धिमा ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन ऊना जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बौल में किया गया था। शिविर के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वयंसेवियों को नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी जानकारियां दी गईं।

इस शिविर में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भरवाईं स्कूल की स्वयंसेवी रिद्धिमा का चयन प्री गणतंत्र दिवस शिविर के लिए हुआ है। इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय पहुंचने पर दोनों स्वयंसेवियों का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य निर्मल कुमार ने कार्यक्रम अधिकारी एवं गणित प्रवक्ता सुनील कुमार तथा सहप्रभारी एवं जीव विज्ञान प्रवक्ता सुरेश कुमारी के साथ दोनों विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने रिद्धिमा को चयन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं, प्री गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयनित न हो पाने वाले दिव्यांश को निराश न होकर आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास और लगन से विद्यार्थी भविष्य में बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

हिमाचली व्यंजनों के मुरीद हुए जर्मन मेहमान



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध खानपान परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद अब विदेशी मेहमानों को भी आकर्षित कर रहा है। गुजरात के एकतानगर (केवड़िया) में आयोजित भारत पर्व 2026 में हिमाचली व्यंजनों ने जर्मनी से आए एक दंपती का दिल जीत लिया। भारत पर्व में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), शिमला की स्टूडियो किचन में पहुंचे इस दंपती ने हिमाचली टीम द्वारा तैयार किए गए विभिन्न पारंपरिक पकवानों का स्वाद चखा। उन्होंने उत्साह के साथ व्यंजनों का आनंद लिया और उनके अनूठे स्वाद, गुणवत्ता तथा विशिष्टता की जमकर सराहना की। दंपती ने हिमाचली खानपान को लेकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए टीम को शानदार प्रतिक्रिया भी दी। इस आयोजन के माध्यम से हिमाचल की पारंपरिक पाक कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। प्रदेश के स्थानीय व्यंजन यहां की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक विविधता को भी प्रदर्शित करते हैं। आईएचएम शिमला की टीम भारत पर्व में हिमाचल की इस विशिष्ट पाक विरासत को देश-विदेश से आने वाले लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जर्मन दंपती की उत्साहजनक प्रतिक्रिया से संस्थान की टीम का उत्साह भी बढ़ा है।

सेंट थॉमस स्कूल में युवाओं को मतदान के अधिकार के प्रति किया जागरूक



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। माय भारत शिमला और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सेंट थॉमस स्कूल, शिमला में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान विद्यार्थियों को लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका और देश के विकास में उनकी भागीदारी के महत्व से अवगत करवाया गया।

कार्यक्रम में माय भारत शिमला के जिला युवा अधिकारी विपिन कुमार, भारतीय खेल प्राधिकरण के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर (वॉलीबॉल) एवं हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, शिलारू के प्रभारी अंकुश कटोच, युवा प्रतीक ओशिन शर्मा तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या शेरोन नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। विद्यालय के युवा पर्यटन क्लब के समन्वयक सुरेंद्र शर्मा ने भी कार्यक्रम के आयोजन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर युवा प्रतीक ओशिन शर्मा ने मतदान के महत्व विषय पर विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मतदान के अधिकार, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी प्रस्तुति से विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक रहने और अपने अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की प्रेरणा मिली।

नशे से दूरी और खेलों से जुड़ने का दिया संदेश



वहीं, अंकुश कटोच ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों को युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार खेल, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों में नियमित भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशे, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन लोकतांत्रिक शपथ के साथ हुआ। विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों तथा जिम्मेदार नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

जुब्बल में 33 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नेहनार-जुब्बल मार्ग पर एक युवक को लगभग 33 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना जुब्बल की टीम ने गुप्त सूचना और नियमित जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। आरोपी की पहचान गोविंद (18) पुत्र बालक राम निवासी लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 33 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस संबंध में पुलिस थाना जुब्बल में तीन नवंबर 2026 को एफआईआर संख्या 58/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 और 85 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में नशे की खेप से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

परीक्षा में असफल अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को बाद में चुनौती नहीं दे सकते : हाई कोर्ट

सरकारी भर्ती में निर्धारित नियमों का पालन जरूरी

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की भागीदारी और बाद में उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार भर्ती के नियमों और निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए उसमें हिस्सा लेता है तो परिणाम घोषित होने के बाद केवल असफलता के आधार पर उसे चुनौती देने का अधिकार नहीं मिल जाता। चयन प्रक्रिया में शामिल होने का निर्णय अभ्यर्थी स्वेच्छा से लेता है। ऐसे में परिणाम प्रतिकूल आने के बाद चयन मानदंडों की वैधता पर सवाल उठाना स्वीकार्य नहीं है। अदालत की इस व्यवस्था को सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के महत्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में ही नियमों और चयन के आधारों पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी अभ्यर्थी स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में शामिल होने और उसमें असफल रहने के बाद उसके नियमों या चयन मानदंडों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया में भागीदारी के बाद परिणाम अपने पक्ष में नहीं आने पर नियमों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने भास्कर सहगल और अन्य की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

यह मामला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 22 जुलाई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन से संबंधित है। इसके तहत अनुबंध आधार पर असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) क्लास-1 राजपत्रित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कुल 2,655 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया, जिसके परिणाम के आधार पर 109 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। इसके बाद आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार लेकर अंतिम परिणाम घोषित किया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हो सका।

अंतिम परिणाम में स्थान नहीं मिलने के बाद भास्कर सहगल और अन्य अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से चयन प्रक्रिया के आधार और साक्षात्कार की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। उनका कहना था कि भर्ती में साक्षात्कार को चयन का एकमात्र आधार बनाया गया, जो उचित नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।

शिमला में निजी कंपनियों के 56 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से दो निजी कंपनियों में कुल 56 पदों के लिए छह और सात नवंबर को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराइक ने बताया कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, मशोबरा में छह नवंबर को सुबह दस बजे छह पदों के लिए साक्षात्कार होगा। इनमें हाउसकीपिंग के तीन और इलेक्ट्रीशियन के तीन पद शामिल हैं। हाउसकीपिंग के लिए 12वीं या स्नातक तथा इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई अनिवार्य है। वेतन 14 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह रहेगा। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक (एनआईआईटी आईएफबीआई) में रिलेशनशिप मैनेजर के 50 पदों के लिए सात नवंबर को सुबह दस बजे जिला रोजगार कार्यालय परिसर, यूएस क्लब में साक्षात्कार होगा। इसके लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक, 21 से 25 वर्ष आयु और पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 26 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। वे शैक्षणिक प्रमाणपत्र और बायोडाटा लेकर निर्धारित समय पर पहुंचें।

डिप्टी सीएम के शिमला न पहुंचने से एचआरटीसी पेंशनरों का फैसला टला



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य वित्तीय मांगों के लिए अभी एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार को भी सरकार उनकी मांगों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकी। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन की ओर से डीए सहित अन्य मांगों से संबंधित फाइल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कार्यालय भेज दी गई थी, लेकिन उनके शिमला में मौजूद न होने के कारण फैसला नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि सरकार पेंशनरों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है। ऐसे में वीरवार को इस संबंध में सकारात्मक निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दरअसल, रामपुर के विधायक नंदलाल के निधन के कारण उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। वह दिल्ली से लौटने के बाद रामपुर चले गए, जिस कारण शिमला में पेंशनरों की मांगों पर बैठक और निर्णय नहीं हो सका। उधर, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे एचआरटीसी पेंशनरों को निगम प्रबंधन ने एक दिन और इंतजार करने के लिए मना लिया।

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने संयुक्त समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री के शिमला लौटने के बाद ही पेंशनरों की मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसके बाद समिति ने बुधवार को प्रस्तावित मुख्यालय घेराव को एक दिन के लिए टालने का फैसला किया। हालांकि पेंशनरों ने स्पष्ट किया है कि यदि वीरवार तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया तो शुक्रवार से निगम मुख्यालय के बाहर परिवार सहित धरना शुरू किया जाएगा। पेंशनरों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उनकी निगाहें अब वीरवार को होने वाले संभावित फैसले पर टिकी हैं।

चार बार विधायक रहे नंद लाल पंचतत्व में विलीन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। रामपुर बुशहर के पूर्व विधायक नंद लाल का बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम यात्रा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया।

भारतेन्दु Classifieds

नाम परिवर्तन

मैं प्रेम लता पत्नी राकेश गांव बागी डाकघर पोएग तहसील आनी जिला कुल्लू हि. प्र. घोषणा करती हूं कि आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम स्वास्तिक वर्मा गलत दर्ज है। अब में आधार कार्ड में अपने पुत्र का सही नाम स्वास्तिक ठाकुर दर्ज करवाना चाहती हूं। संबंधित नोट करें।

न्यूज ब्रीफ

रुद्रप्रयाग में जानलेवा हमले के मामले में एक गिरफ्तार



भारतेन्दु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। जखोली क्षेत्र में पत्नी से मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपित मानवेन्द्र सिंह राणा निवासी पाला कुरााली को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 21 अगस्त 2026 को सरोजनी देवी ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपित ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। शुरुआत में राजस्व पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर जांच नियमित पुलिस को सौंपी गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 109(1), 117(2) और 115(2) भी जोड़ी गईं। पुलिस ने चार नवंबर को आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की।

दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी



भारतेन्दु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। दीपावली और त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर टीम ने सिल्ली, अगस्त्यमुनि और विजयनगर में मिठाई की दुकानों और डेयरी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान पांच प्रतिष्ठानों से बालूशाही, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, बीकानेरी बर्फी और गाय के दूध के नमूने लिए गए। इन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला भेजा जाएगा। एक दुकान में एक्सपायरी जीरा और पापड़ मिलने पर उन्हें मौके पर नष्ट कराया गया। कुछ प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की कमी मिलने पर संचालकों को चेतावनी दी गई। विभाग ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही।

बच्ची की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा

पौड़ी में आक्रोशित लोगों व ग्रामीणों ने खांडयूसैंण में लगाया जाम



भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। खांडयूंसैंण में गुलदार के हमले में पांच वर्षीय बच्ची की मौत के बाद बुधवार को ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने पौड़ी-देवप्रयाग मार्ग पर जाम लगाकर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने, गश्त बढ़ाने और प्रभावित गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। जिलाधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीण पौड़ी पहुंचे और एजेंसी चौक पर भी जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से गुलदार की सक्रियता के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। वहीं, विधायक राजकुमार पोरी ने घटना स्थल पर कुछ लोगों पर उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया।

यूआईआईडीबी को लेकर भ्रामक प्रचार पर सरकार ने तथ्यों से दिया जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। यूआईआईडीबी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी भूमि की मनमानी बिक्री नहीं, बल्कि उसका उपयोग निवेश, रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए करना है। अगले दो-तीन माह में केवल छह-सात चयनित भूमि पार्सल की बिडिंग की तैयारी है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश से सात से आठ हजार प्रत्यक्ष और 10 से 15 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इससे राज्य को हर माह करीब 300 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है। चौबटिया, धनोल्टी, आईडीपीएल और एचएमटी की जमीनों का वर्तमान प्रस्तावों से संबंध नहीं है। उन्होंने भ्रामक प्रचार के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा करने की अपील की।

टनकपुर में 14.25 करोड़ रुपये से बनेगा आधुनिक मीडिया सेंटर



भारतेन्दु संवाददाता, चंपावत। टनकपुर में 14 करोड़ 25 लाख 52 हजार रुपये की लागत से आधुनिक मीडिया सेंटर और गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत बनने वाले इस भवन को एक साल के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि भवन का निर्माण निर्धारित समय में पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित भवन के भूतल पर पार्किंग और दो कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। प्रथम तल पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया सेंटर होगा। ऊपरी दो मंजिलों पर गेस्ट हाउस तैयार किया जाएगा, जिसमें चार सुइट और दो सामान्य अतिथि कक्ष होंगे। इससे पत्रकारों को बैठकों, संवाद और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

ग्रामीण सड़कों की बदहाली पर यूकेडी ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन



भारतेन्दु संवाददाता, थराली। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने बुधवार को ग्रामीण सड़कों की बदहाली और लंबित निर्माण कार्यों को लेकर लोनिवि कार्यालय थराली में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की और अधिशासी अभियंता मनीष डोगरा को ज्ञापन सौंपा। इसमें नारायणबगड़ की 12, थराली की छह और देवाल विकासखंड की 15 सड़कों के सुधारीकरण व डामरीकरण की मांग उठाई गई। यूकेडी ने कहा कि कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं और आपदा के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण भी नहीं हुआ है। इस दौरान अधिकारियों के साथ सड़कों और मोटर पुलों की समस्याओं पर चर्चा हुई। अधिशासी अभियंता ने डिविजन स्तर के कार्य प्राथमिकता से कराने और शासन स्तर के मामलों के निस्तारण का आश्वासन दिया।

युवा उद्यमियों ने प्रस्तुत किए 750 से अधिक नए विचार

यूपीईएस के युवा उद्यमिता मंच पर 23 राज्यों के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

राज्य ब्यूरो

देहरादून। यूपीईएस के रनवे इनक्यूबेटर की ओर से आयोजित फ्यूचर फाउंडर्स चैलेंज 2026 का दूसरा संस्करण एक से तीन नवंबर तक आयोजित किया गया। इसमें देश के 23 राज्यों के 100 से अधिक शहरों के 150 से ज्यादा स्कूलों के 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 500 से अधिक टीमों ने 750 से ज्यादा व्यावसायिक और नवाचार आधारित विचार प्रस्तुत किए। इनमें से चयनित 30 टीमों को देहरादून स्थित यूपीईएस परिसर में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के लिए पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई थी। रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल ने पहला स्थान हासिल कर डेढ़ लाख रुपये का पुरस्कार जीता।

दस फाइनलिस्ट टीमों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मान



लुधियाना के बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दूसरा स्थान और एक लाख रुपये मिले, जबकि लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल कर 50 हजार रुपये प्राप्त किए। इसके अलावा सात टीमों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25-25 हजार रुपये के पुरस्कार दिए गए। शीर्ष तीन टीमों को टेकऑफ 6.0 के तहत पूर्व-इन्क्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान दस फाइनलिस्ट टीमों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

विजेताओं को पांच लाख के पुरस्कार

विशेषज्ञों और मार्गदर्शकों ने विद्यार्थियों को व्यावसायिक विचारों को व्यावहारिक स्वरूप देने, उद्यमिता की चुनौतियों को समझने और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यूपीईएस प्रबंधन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य स्कूली स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों को देश के स्टार्टअप परिवेश से जोड़ना है।

केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब, समापन की ओर बढ़ी यात्रा, जयकारों से गूंज रहा धाम

केदारनाथ यात्रा में अब तक 18,91,500 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

राज्य ब्यूरो



रुद्रप्रयाग। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने के साथ ही बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। वर्ष 2026 की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मौसम अनुकूल रहने से भक्त हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले रहे हैं। मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धालु पैदल मार्ग, घोड़ा-खच्चर, डंडी-कंडी और हेलीकाप्टर सेवाओं के माध्यम से धाम पहुंच रहे हैं।

केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 11 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यात्रा समाप्त होने में अब केवल आठ दिन शेष हैं। इस वर्ष अब तक कुल 18,91,500 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

यातायात नियंत्रण पर पुलिस की नजर

यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक ठहरने, खानपान, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया गया है। पुलिस भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षित आवाजाही पर नजर रख रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने श्रद्धालुओं से पर्याप्त गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां साथ रखने तथा यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की अपील की है। साथ ही प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यात्रा करने की सलाह दी है।

कांग्रेस के आरोपों पर उनियाल का पलटवार

जमीनों की बिक्री और निजीकरण के आरोप निराधार : सुबोध उनियाल

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) के तहत सरकारी भूमि के उपयोग को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निवेश परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली जमीनों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। निजी निवेशकों को केवल निर्धारित अवधि तक विकास और संचालन का सीमित अधिकार दिया जाएगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर जमीन राज्य को वापस मिलेगी।

उनियाल ने कहा कि आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में 1500 से 2000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे पांच हजार से अधिक प्रत्यक्ष और 10 हजार से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य को 200 से 250 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि एचएमटी, आईडीपीएल, लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों और उद्यान विभाग की जमीनें संबंधित विभागों के पास सुरक्षित हैं। इन संपत्तियों को बेचने की कोई योजना नहीं है।

मंत्री ने कांग्रेस पर निवेश और विकास को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व सुरक्षित रखते हुए उनका उपयोग पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं, किसानों और कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा।

मोहब्बेवाला में कार पर पलटा ट्रक, चार की मौत

मोहब्बेवाला चौक बना मौत का हाईवे!



भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला चौक पर बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह वर्षीय बच्चा सुरक्षित बच गया। करीब साढ़े तीन बजे एक बेकाबू कंटेनर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कबाड़ में तब्दील हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार के क्षतिग्रस्त हिस्सों को कटर की मदद से काटकर घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल चार लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान मिश्रेष कपूर (38), निशा आनंद कपूर (38), किरण कपूर (63) और कार चालक नीरज के रूप में हुई है। वहीं, छह वर्षीय माहेर कपूर को पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार सवार सभी लोग सहारनपुर से देहरादून आ रहे थे।

मोहब्बेवाला चौक की सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर मोहब्बेवाला चौक और आसपास के हाईवे क्षेत्र में सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते। सड़क की बनावट, भारी वाहनों की आवाजाही, यातायात प्रबंधन, संकेतकों और वाहनों की गति नियंत्रित करने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद दुर्घटना संभावित क्षेत्र का तकनीकी सुरक्षा ऑडिट कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है।

चार मौतों ने सड़क सुरक्षा पर फिर चेताया

स्थानीय लोगों का सवाल है कि बार-बार दुर्घटनाओं के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। चार लोगों की मौत ने पूरे शहर को सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर कदम उठाने की चेतावनी दी है। अब संबंधित विभागों से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।

दो महिलाओं समेत चार की मौत; छह वर्षीय बच्चा सुरक्षित



कांग्रेस पहले अपने शासनकाल का भूमि रिकॉर्ड सार्वजनिक करे : भट्ट

भारतेन्दु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। भाजपा जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने कांग्रेस के भूमि बचाओ-धामी हटाओ अभियान को राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जमीनों के आवंटन को लेकर कई सवाल उठे थे। हरीश रावत सरकार के समय नानीसार में 7.061 हेक्टेयर पंचायत भूमि 1200 रुपये सालाना किराये पर 30 वर्ष के लिए देने और धौलास में शैक्षणिक संस्थान के नाम पर ली गई करीब 20 एकड़ जमीन के छोटे भूखंडों में बंटने का मामला इसका उदाहरण है।



- **कांग्रेस अपनी डूबती राजनीतिक जमीन बचाने के लिए चला रही भूमि बचाओ अभियान : भट्ट**
- **उत्तराखंड में निवेश का विरोध कर रही कांग्रेस : भारत भूषण भट्ट**

भट्ट ने कहा कि धामी सरकार जमीन बेच नहीं रही, बल्कि निवेशकों को निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर दे रही है। सरकार ने करीब 13 हजार एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई है और सख्त भू-कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेती योग्य भूमि सीमित है। ऐसे में बंद पड़े उद्योगों, खाली सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीनों पर निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे युवाओं का पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को विरोध की राजनीति के बजाय भूमि सुरक्षा के साथ निवेश और विकास की जरूरत है।

केदारताल हिमस्खलन हादसे में चार ट्रैकर्स के शव बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन की चपेट में आकर लापता हुए आठ सदस्यीय दल के चार लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। महिलाओं की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी सगी बहनों दीपिका वर्मा (29) और वर्तिका वर्मा (28) के रूप में हुई है। वहीं, दो पुरुषों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी रिंटू मंडल और उदय घोष के रूप में बताई गई है। हालांकि, इनकी आधिकारिक पुष्टि परिजनों के पहुंचने के बाद होगी। बुधवार को एसडीआरएफ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान दो और शव बरामद किए। इससे पहले मंगलवार को एक महिला और एक पुरुष का शव मिला था। खराब मौसम के कारण बुधवार दोपहर तीन बजे के बाद बचाव अभियान रोकना पड़ा। शेष लापता लोगों की तलाश के लिए गुरुवार को फिर अभियान चलाया जाएगा।

क्या उत्तराखंड में... पतंजलि घी के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराई जाएगी?

क्या देवभूमि उत्तराखंड में भी पतंजलि के गाय के घी की जांच हो सकती है?

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून



पतंजलि घी पर महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई, 20.20 लाख का स्टॉक जब्त।

पतंजलि के गाय के घी पर महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई के बाद उत्तराखंड में भी उत्पाद की गुणवत्ता और लेबलिंग की जांच की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पतंजलि आयुर्वेद के सुपर वितरक मेसर्स दिव्य महावितरक के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर 2,279.7 लीटर गाय का घी जब्त किया है। जब्त घी की अनुमानित कीमत 20.20 लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान घी के 4,032 पैकेट कब्जे में लिए गए। अधिकारियों को उत्पाद की लेबलिंग और नाम से जुड़ी जानकारी में संभावित अनियमितताओं के साथ मिलावट की आशंका भी मिली थी। इसके बाद घी के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं।

प्रारंभिक कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है। हालांकि, प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले मिलावट की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस मामले के बाद उत्तराखंड में भी खाद्य सुरक्षा विभाग से कई सवाल पूछे जा रहे हैं।

क्या जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे?....

क्या स्थानीय वितरकों और स्टॉकिस्टों के यहां निरीक्षण किया जाएगा?

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 38 के तहत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने ले सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में इस मामले में किसी विशेष कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।

तैयारी — कनखल की 150 साल पुरानी इमारतें पीले रंग से सजेंगी, सौंदर्यीकरण में तेजी

कुंभ-2027 की तैयारी में संवरने लगी धर्मनगरी हरिद्वार



भारतेन्दु संवाददाता, हरिद्वार। कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के बीच धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप धीरे-धीरे निखरने लगा है। कुंभ मेले के बजट से शहर में पांच स्थायी पुल, 4.5 किलोमीटर लंबे गंगा घाट और कई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही शहर को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए रंगाई-पुताई तथा सौंदर्यीकरण के कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। प्राचीन इमारतों को एकरूप रंगों से सजाया जा रहा है, जबकि हाईवे के फ्लाईओवर और रेल अंडरपास की दीवारों पर सनातन संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी की जा रही है।

सौंदर्यीकरण का उद्देश्य हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को शहर की धार्मिक पहचान, प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। हरकी पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों और कनखल क्षेत्र में विशेष रूप से काम कराया जा रहा है। कनखल की करीब 150 साल पुरानी इमारतों को एकरूप स्वरूप देने के लिए पीले रंग से रंगाई-पुताई की जा रही है। वहीं, दुकानों और प्रतिष्ठानों के बोर्ड भी भगवा रंग में तैयार किए जा रहे हैं।

नवंबर के अंत तक पूरा होगा सौंदर्यीकरण

अपर कुंभ मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि कुंभ मेले के मद्देनजर हरिद्वार को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। शहर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता देते हुए सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है। कनखल की पुरानी इमारतों को एकरूप रंगों से सजाने के साथ प्रमुख मार्गों और फ्लाईओवर पर धार्मिक चित्रकारी कराई जा रही है।

कनखल की प्राचीन इमारतें यहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में इनके सौंदर्यीकरण को शहर की पहचान निखारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।एचआरडीए, एनएचएआई सहित कई विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कार्यों को नवंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सौंदर्यीकरण के कार्यों से शहर की बदलती तस्वीर को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।

हाईवे के प्रमुख फ्लाईओवर और रेल अंडरपास की दीवारों पर देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों और साधु-संतों के चित्र उकेरे जा रहे हैं। चित्रकारी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शहर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को हरिद्वार की आध्यात्मिक पहचान का अनुभव हो सके।

23 नवंबर से शुरू होगा श्रीनगर का प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेला

बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने की समीक्षा



भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। श्रीनगर में 23 नवंबर से आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को नगर निगम सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए व्यवस्थाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधा, सुरक्षा तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।

मंत्री ने पुलिस विभाग को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, विद्युत विभाग को पर्याप्त रोशनी तथा जल संस्थान को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। नगर निगम को मेला स्थल, बाजार और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण तथा शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने खड़े दीये जलाने के दिन संबंधित स्थल पर अलाव की व्यवस्था और अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंदिर की पुताई समय पर पूरी कराने, भंडारे की व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने तथा स्नान स्थल पर सुधारीकरण और फिसलन रोकने के इंतजाम करने को भी कहा।

पंजाब दा करोड़पति क्विज के लिए डिजिटल मंच तैयार, जल्द शुरू होगी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता के लिए मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और सुरक्षित प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतियोगिता को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संचालित करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके तकनीकी विकास और संचालन की जिम्मेदारी गुड गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक लोगों के पंजीकरण से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी।



सरकार का उद्देश्य क्विज मुकाबले के संचालन को व्यवस्थित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए तैयार किए जाने वाले मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को प्रतियोगिता की विभिन्न गतिविधियों के संचालन का प्रमुख माध्यम बनाया जाएगा। प्रतिभागियों को पंजीकरण और प्रतियोगिता से जुड़ी जरूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ प्रतियोगिता के संचालन में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रतियोगिता के लिए तैयार की जाने वाली डिजिटल प्रणाली में प्रश्न बैंक प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। इसके लिए सुरक्षित प्रश्न बैंक प्रबंधन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्नों के प्रबंधन और संचालन को तकनीकी रूप से व्यवस्थित किया जा सकेगा। प्रश्न बैंक की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि प्रतियोगिता की प्रक्रिया में गोपनीयता और विश्वसनीयता बनी रहे। क्विज मुकाबले के संचालन में अलग-अलग चरणों से जुड़ी जानकारियों को डिजिटल माध्यम से संभालने की योजना है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिये प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से जोड़ने के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी प्रक्रिया को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। इससे प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों का प्रबंधन एक ही डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकेगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिभागियों की शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। इस डैशबोर्ड के माध्यम से संबंधित विभाग प्रतियोगिता के संचालन और उससे जुड़ी गतिविधियों की निगरानी कर सकेगा। ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था से प्रतिभागियों को अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का माध्यम मिलेगा। गुड गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को तकनीकी जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद प्रतियोगिता के लिए जरूरी डिजिटल ढांचा तैयार करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। विभाग मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, प्रश्न बैंक प्रबंधन, शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग से जुड़ी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी संभालेगा।

'पंजाब दा करोड़पति' क्विज मुकाबले को डिजिटल तरीके से आयोजित करने की योजना से प्रतियोगिता के संचालन में तकनीक की भूमिका अहम होगी। पंजीकरण से लेकर परीक्षा और परिणाम तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से प्रतिभागियों को अलग-अलग चरणों के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध होगा। वहीं, विभागीय स्तर पर भी प्रतियोगिता की निगरानी और प्रबंधन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल के तहत प्रतियोगिता के लिए एक ऐसा डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों से जुड़ी प्रक्रिया और प्रशासनिक निगरानी की सुविधाएं शामिल होंगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल तैयार होने के बाद क्विज मुकाबले के संचालन को इसी तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

डी.ए. कर्मचारियों का अधिकार, सरकार की मेहरबानी नहीं : मास्टर कैडर यूनियन

भारतेंदु संवाददाता, पठानकोट। मास्टर कैडर यूनियन पंजाब ने राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए 8 प्रतिशत और बाद में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) को सरकार की मेहरबानी मानने से इनकार किया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी किसी सरकारी तोहफे या दिवाली की सौगात के रूप में नहीं हुई, बल्कि अदालत की सख्ती और कर्मचारियों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद संभव हो पाई है। कर्मचारियों को उनका जायज हक हासिल करने के लिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।



यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले अदालत से राहत पाने के लिए कर्मचारियों को 8 प्रतिशत डीए जारी किया था। इसके बाद जब माननीय अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के निर्देश दिए तो सरकार ने दोबारा अदालती कार्रवाई से बचने के प्रयास में 3 प्रतिशत डीए जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों को उनका अधिकार स्वेच्छा से देने के बजाय अदालती दबाव में फैसले ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह, महासचिव अरजिंदर सिंह कलेर, उपाध्यक्ष रमन कुमार, वित्त सचिव बलविंदर सिंह और प्रेस सचिव संदीप ने संयुक्त बयान में कहा कि यदि सरकार वास्तव में कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर होती तो उन्हें अपने जायज अधिकारों के लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार उनके अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। यह रवैया कर्मचारी वर्ग के लिए चिंता का विषय है। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी और जायज अधिकार है, न कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला कोई उपहार। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिशत डीए जारी करने को भी कर्मचारी अदालती कार्रवाई से बचने और अगली सुनवाई तक समय हासिल करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं।

मास्टर कैडर यूनियन ने कर्मचारी वर्ग से अपील की कि वे डीए बढ़ोतरी को सरकार की मेहरबानी या दिवाली के तोहफे के रूप में न देखें। नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई के साथ-साथ संगठनात्मक संघर्ष भी जारी रखा जाएगा। यूनियन ने स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों को उनके सभी जायज हक नहीं मिल जाते, तब तक आंदोलन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ जारी रहेगा। यूनियन ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता ही उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती देगी। संगठन सरकार से लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने की मांग करता रहेगा।

हरियाणा की भूमि पूलिंग नीति से चंडीगढ़ के 22 गांवों के किसानों में जगी उम्मीद

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की वर्ष 2026 की भूमि पूलिंग नीति में जमीन मालिकों को 50 प्रतिशत विकसित जमीन देने के फैसले से चंडीगढ़ के 22 गांवों के किसानों की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं। लंबे समय से भूमि पूलिंग नीति लागू करने की मांग कर रहे किसानों को अब उम्मीद है कि चंडीगढ़ प्रशासन भी हरियाणा की तर्ज पर उन्हें विकास में हिस्सेदार बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगा।



चंडीगढ़ पेंडू विकास मंच ने हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मंच ने यूटी प्रशासन से सवाल किया है कि जब हरियाणा में किसानों को विकास का भागीदार बनाया जा सकता है तो चंडीगढ़ में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? मंच का कहना है कि चंडीगढ़ के गांवों के किसानों को भी अपनी जमीन के बदले विकसित जमीन में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी 22 गांवों में भूमि पूलिंग नीति तत्काल लागू की जानी चाहिए। हरियाणा सरकार की नई भूमि पूलिंग नीति में जमीन मालिकों को 50 प्रतिशत विकसित जमीन में हिस्सेदारी देने का प्रावधान किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले से जमीन मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इसी आधार पर चंडीगढ़ के किसान भी अपने लिए ऐसी ही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ के 22 गांवों में भूमि पूलिंग नीति को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन कब तक इस दिशा में फैसला लेगा। चंडीगढ़ पेंडू विकास मंच ने प्रशासन से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और नीति तैयार करने की मांग की है।

मंच का मानना है कि विकास योजनाओं में गांवों और किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भूमि पूलिंग के माध्यम से किसानों को विकसित जमीन में हिस्सेदारी मिलने से वे भी शहर के विकास से जुड़ सकेंगे। हरियाणा सरकार के फैसले के बाद चंडीगढ़ के किसानों की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

चंडीगढ़ से पटना की उड़ान का किराया आसमान पर पहुंचा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। दीपावली और छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। त्योहारों के चलते चंडीगढ़ से बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया काफी बढ़ गया है। चंडीगढ़-पटना उड़ान का टिकट 25 हजार रुपये के पार पहुंच गया है। इससे हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता और मुंबई अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग के चलते इन रूटों पर हवाई टिकटों के दाम बढ़े हैं। वहीं, ट्रेनों में भी कन्फर्म सीटें नहीं मिल रही हैं। कई यात्रियों को पहले से टिकट बुक कराने के बावजूद यात्रा को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। ट्रेन और फ्लाइट दोनों का सफर महंगा होने से यात्रियों के सामने विकल्प सीमित हो गए हैं। ऐसे में लोग अब बसों का सहारा ले रहे हैं। त्योहारों पर घर पहुंचने की चाह रखने वाले यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाने या लंबी यात्रा करने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए इस बार त्योहारों का सफर बजट पर भारी पड़ रहा है। हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों और ट्रेनों में सीटों की कमी के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में दिक्कत आ रही है।

एलपीयू प्रोटेस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

राज्य सरकार को 72 घंटे में जांच से जुड़ी रिपोर्ट केंद्र को देनी होगी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) से जुड़े प्रोटेस्ट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पंजाब सरकार को 72 घंटे के भीतर जांच से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट मिलने के सात दिन के भीतर यह फैसला करने को कहा है कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी जानी चाहिए या नहीं।



बुधवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का आदेश दिया। वहीं, केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह राज्य सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद सात दिनों के अंदर एनआईए जांच को लेकर अपना निर्णय ले।

यह जनहित याचिका एलपीयू के छात्र रवि राज की ओर से दायर की गई है। याचिका में विश्वविद्यालय से जुड़ी घटना की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता का पक्ष है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की उचित पड़ताल हो सके।

हाईकोर्ट के इन निर्देशों के बाद अब पंजाब सरकार को पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र के समक्ष रखनी होगी। इसके बाद केंद्र सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर तय करेगी कि मामले की जांच एनआईए को सौंपने की आवश्यकता है या नहीं। इस तरह अदालत ने जांच एजेंसी के चयन को लेकर एक समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की है। मामले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66एफ लगाए जाने का भी उल्लेख है। यह धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित अपराधों से जुड़ी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस धारा के तहत लगाए गए आरोपों और जांच के विस्तृत तथ्यों का पूरा ब्योरा सामने नहीं आया है।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबकी नजर पंजाब सरकार की रिपोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले पर रहेगी। राज्य सरकार को 72 घंटे में रिपोर्ट देनी है, जबकि केंद्र को रिपोर्ट मिलने के सात दिन के भीतर एनआईए जांच पर निर्णय लेना होगा। अदालत के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि मामले की जांच को लेकर अगला कदम तय समयसीमा में उठाया जाना है।

बलटाना मार्केट में आग से भारी नुकसान दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

भारतेंदु संवाददाता, जीरकपुर। बलटाना की फर्नीचर मार्केट में बुधवार को एक बार फिर भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से करीब 22 फर्नीचर शेड जलकर राख हो गए। इन शेड में रखा लाखों रुपये का फर्नीचर और अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को अपना सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही मार्केट में अफरा-तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। देखते ही देखते आग ने आसपास के कई शेड को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानदारों ने अपने स्तर पर सामान बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तेजी के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की आठ गाड़ियों को इसे बुझाने के लिए लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

हालांकि, तब तक करीब 22 फर्नीचर शेड और उनमें रखा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। इस घटना के बाद मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। फर्नीचर मार्केट में लकड़ी, फोम और अन्य ज्वलनशील सामान बड़ी मात्रा में रखा जाता है। ऐसे में आग लगने पर उसके तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। दुकानदारों को हुए नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है।

सरकारी और संस्थागत जमीन के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण का मामला

मोगा की आप विधायक अमनदीप कौर के सात ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पंजाब में मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा से जुड़े सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सरकारी और संस्थागत संपत्तियों के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई है। जांच का संबंध नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मामले से भी बताया जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तलाशी के दौरान बरामदगी या जांच के निष्कर्षों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। अमनदीप कौर अरोड़ा मोगा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने उन्हें 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसी वजह से उनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ईडी ने बुधवार को पंजाब में एक साथ सात स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी की कार्रवाई का मुख्य आधार सरकारी और संस्थागत जमीन के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी जांच है। मामले में जमीन के रिकॉर्ड और इंतकाल से संबंधित अनियमितताओं की बात भी सामने आई है।



चंडीगढ़ में अतिक्रमण रोकने के लिए निगम की नई पहल

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में सड़कों, फुटपाथों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रेहड़ी-फड़ी और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने नई पहल की है। अब शहरवासी ऐसी गतिविधियों की शिकायत सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से निगम तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने नंबर जारी किया है। शहर के किसी भी हिस्से में यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाता है या सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करता है, तो नागरिक उसकी फोटो लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। शिकायत के साथ संबंधित स्थान की सटीक लोकेशन देना भी जरूरी होगा, ताकि निगम की टीम मौके तक आसानी से पहुंच सके। नगर निगम के अनुसार, व्हाट्सएप पर शिकायत और तस्वीर मिलने के बाद संबंधित टीम को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।

झोटा हत्याकांड में नया मोड़, दुकान गिराने पर 1200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर

भारतेंदु संवाददाता, मानसा। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार की दुकान को ध्वस्त किए जाने के मामले में की गई है। पुलिस ने इस घटना को लेकर 1000 से 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।



जानकारी के अनुसार, परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में अश्वनी कुमार मुख्य आरोपी है। उसकी कैमिस्ट शॉप को गिराए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। दुकान ध्वस्त किए जाने की घटना को लेकर मानसा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में आरोपितों की पहचान अभी सामने नहीं आई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद झोटा हत्याकांड से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

हत्या के आरोपी की दुकान गिराए जाने की घटना के संबंध में पुलिस अब दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच करेगी। 1000 से 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने से घटना में शामिल लोगों की पहचान करना पुलिस के लिए अहम रहेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने दुकान गिराने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवार को मिला अंतिम संस्कार का अधिकार

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत के आदेश के बाद अब दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार 5 नवंबर को मोगा जिले के उनके पैतृक गांव भामे कलां में किया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम संस्कार को लेकर परिवार और प्रशासन के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर हो गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खुली अदालत में ही अपना आदेश सुना दिया। अदालत के आदेश की लिखित प्रति बुधवार शाम चार बजे तक जारी किए जाने की बात कही गई है। यह आदेश दलजीत सिंह की बहन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया गया है। परिवार की ओर से अंतिम संस्कार को लेकर अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी।



इससे पहले हाईकोर्ट ने दलजीत सिंह का पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में करवाने का आदेश दिया था। अदालत ने पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार परिवार और करीबियों की मौजूदगी में सम्मानजनक तरीके से कराया जाए। अदालत ने मामले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। इसके तहत प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है।

अदालत की ओर से पहले दिए गए निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि परिवार को अपने तरीके से अंतिम विदाई देने का अवसर मिले और पूरी प्रक्रिया सम्मानजनक ढंग से संपन्न हो। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद पांच नवंबर को भामे कलां में दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के सदस्य और करीबी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मामले में अदालत के हस्तक्षेप के बाद अंतिम संस्कार की तारीख और स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अदालत के आदेश के बाद परिजनों को मिला सम्मानजनक विदाई का अवसर।

विवाद

1984 दंगों के मुद्दे पर पंजाब में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

राहुल गांधी की इंसाफ रैली से कांग्रेस का चुनावी आगाज

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इस मुद्दे को लेकर अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। बुधवार को एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगरूर में 'इंसाफ रैली' के माध्यम से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा चंडीगढ़ में 'जख्म 84 दे' नाम से एक दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित कर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है।

राहुल गांधी की संगरूर में होने वाली रैली को पंजाब में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली के जरिए पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाएगी। वहीं, भाजपा ने भी 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस से सवाल करने की तैयारी की है। चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले कॉन्क्लेव में 1984 की हिंसा, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए चली चार दशक लंबी कानूनी लड़ाई और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।



भाजपा का 'जख्म 84 दे' कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है, जब कांग्रेस पंजाब में चुनावी अभियान को गति देने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से 1984 के दंगों से जुड़े सवालों को फिर से राजनीतिक चर्चा में लाना चाहती है। खास तौर पर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लंबी प्रक्रिया और उनके पुनर्वास का विषय कार्यक्रम के केंद्र में रहेगा। पंजाब की राजनीति में 1984 के दंगों का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। इस घटना से प्रभावित परिवारों के लिए न्याय और पुनर्वास की मांग समय-समय पर उठती रही है। ऐसे में चुनाव से पहले इस मुद्दे पर दोनों प्रमुख दलों के कार्यक्रमों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुधवार को संगरूर और चंडीगढ़ में होने वाले दोनों कार्यक्रमों के कारण राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। एक तरफ राहुल गांधी रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ भाजपा कॉन्क्लेव के माध्यम से 1984 के दंगों से जुड़े सवाल उठाएगी।

दोनों दलों के कार्यक्रम एक ही दिन होने से पंजाब में चुनावी माहौल के साथ 1984 का मुद्दा भी फिर चर्चा में आ गया है। राजनीतिक जानकारों की नजर अब इन दोनों कार्यक्रमों पर रहेगी कि इनके जरिए कौन-सा दल जनता के बीच अपनी बात अधिक प्रभावी ढंग से रख पाता है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 1984 के दंगों का मुद्दा पंजाब की राजनीति में फिर अहम स्थान हासिल कर रहा है।

मोदी को चुनौती नहीं दे पा रही कांग्रेस, मकसद सिर्फ देश में अस्थिरता पैदा करना : राम माधव

बोले, बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं को सत्ता परिवर्तन का मॉडल मान रही कांग्रेस

भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से चुनौती देने में असमर्थ विपक्षी पार्टी अब सत्ता हासिल करने के लिए देश में अराजकता और अस्थिरता का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य अब केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जानबूझकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप भी लगाया।

मंगलवार को जम्मू के त्रिकुटानगर स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम माधव ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष देश में सरकार बदलने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय अराजकता का रास्ता अपनाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता सत्ता परिवर्तन (रिजीम चेंज) की बातें कर रहे हैं और बांग्लादेश तथा नेपाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को भारत में सरकार बदलने के मॉडल के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बनाने और बदलने का अधिकार जनता के पास होता है। इसके लिए चुनाव ही सबसे उचित और संवैधानिक माध्यम है। दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए राम माधव ने कहा कि यदि कांग्रेस भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए 50 हजार लोगों को एकत्र कर सकती है तो भाजपा भी उसके आरोपों की सच्चाई जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी।



घुसपैठियों को वोट का अधिकार क्यों : राम माधव

उन्होंने कहा कि भाजपा पांच लाख गांवों तक पहुंचेगी और करीब सौ करोड़ लोगों को कांग्रेस के दुष्प्रचार की वास्तविकता से अवगत कराएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जनता के बीच अपना पक्ष रखेगी। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा उपाध्यक्ष ने घुसपैठ का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। जम्मू में रोहिंग्या लोगों के बसने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह चाहती है कि अवैध रूप से देश में आए लोगों को भी भारतीय नागरिकों की तरह मतदान का अधिकार मिल जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है।

कांग्रेस की चुनावी भूमिका पर राम माधव ने उठाए सवाल

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर राम माधव ने दावा किया कि करीब छह करोड़ नाम ऐसे हैं, जिनसे जुड़े मतदाता दूसरी जगहों पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हटाए गए नामों की जांच की जा रही है और पात्र लोगों को दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के माध्यम से नया पंजीकरण या आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि पिछले दस वर्षों में मतदाता सूची में करीब 2.5 करोड़ नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। कांग्रेस पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए राम माधव ने इंदिरा गांधी के चुनाव से जुड़े पुराने मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने याद दिलाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1987 के विधानसभा चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस की चुनावी भूमिका पर सवाल उठाए।

सांकू को 13 और चांगथांग को 10 सीटें प्रस्तावित,

लद्दाख में परिषदों की सीटें 52 से बढ़कर होंगी 100, आठ जिलों के परिसीमन पर सुनवाई शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, लेह

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के गठन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश के आठ जिलों में परिषदों के लिए प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के मसौदे पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई बुधवार से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दो दिवसीय जिला-वार कार्यक्रम घोषित किया है। चार और पांच नवंबर को संबंधित व्यक्तियों, पंचायत प्रतिनिधियों और संगठनों को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद परिसीमन की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है।

लद्दाख में वर्तमान में आठ जिले हैं। इनमें लेह और कारगिल के अलावा हाल ही में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास और सांकू को नए जिलों के रूप में गठित किया गया है। प्रशासन ने पिछले महीने सभी आठ जिलों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत नए जिलों के साथ लेह और कारगिल में भी निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक हो गया है।



◆ लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का विस्तार

प्रस्तावित परिसीमन में परिषदों की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 100 करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लेह में 22, कारगिल में 21, सांकू में 13 और चांगथांग में 10 सीटें प्रस्तावित हैं। वहीं नुब्रा, शाम और जांस्कर में नौ-नौ तथा द्रास में सात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने का प्रस्ताव है। परिसीमन के मसौदे पर करीब 600 आपत्तियां और सुझाव मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने इनकी आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है।

लेह स्थित एलएएचडीसी न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में नुब्रा की सुनवाई दोपहर 12:30 से 1:30 बजे, चांगथांग की 2:30 से 3:30 बजे, शाम की 3:30 से 4:30 बजे और लेह की 4:30 से 5:30 बजे तक होगी।

पांच नवंबर को कारगिल क्षेत्र के जिलों की सुनवाई निर्धारित है। द्रास के लिए सुबह 10 से 11 बजे, कारगिल के लिए 11 से 12 बजे, सांकू के लिए दोपहर 12 से एक बजे और जांस्कर के लिए एक से दो बजे तक का समय तय किया गया है। सुनवाई के बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुबारक गुल का बड़ा संदेश, बोले- सही समय पर रखूंगा पक्ष

मुबारक गुल के तेवर से नेकां में हलचल बोले- मैं फाइटर हूं, संघर्ष जारी रखूंगा

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रही खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुबारक गुल ने अपनी प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी है। चार नवंबर को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल वह न तो कोई सफाई देंगे और न ही कोई खुलासा करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों, साथियों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को इस फैसले की प्रमुख वजह बताया। गुल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए वह एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते थे, लेकिन पिछले कई दशकों से उनके साथ खड़े रहे कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।



उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वह सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखेंगे और इसकी जानकारी भी दी जाएगी।

अपने राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए गुल ने कहा कि वह एक फाइटर हैं और पहले भी संघर्ष करते रहे हैं तथा आगे भी अपने मकसद के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, बारामुला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर से उनके समर्थन में पहुंचे लोगों का आभार जताया। गुल ने कहा कि पिछले 55 वर्षों से लोग उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद किया। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने के बाद मुबारक गुल की नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद 27 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें पार्टी महासचिव नियुक्त किया था।

यह नियुक्ति अली मुहम्मद सागर के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद हुई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर को पार्टी की ओर से जारी एक अन्य आदेश में सागर को अगले आदेश तक महासचिव बने रहने का निर्देश दिया गया। इससे गुल की संगठनात्मक भूमिका को लेकर असमंजस पैदा हो गया। उन्होंने चार नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन घटनाक्रमों पर खुलकर अपनी बात रखने का संकेत दिया था। अब प्रेस वार्ता स्थगित होने से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

दुबई से चल रहा था करोड़ों का नेटवर्क जम्मू में आकाश के जिम्मे थी कमान

भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में 111 सिम कार्ड और करीब 60 फर्जी बैंक खातों के जरिये 70 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का मामला अब अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ता नजर आ रहा है। जम्मू पुलिस की करीब तीन महीने से चल रही जांच में इस पूरे नेटवर्क का दुबई कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, नेटवर्क का स्थानीय संचालन मुख्य आरोपी आकाश आनंद करता था, जबकि इसका असली मास्टरमाइंड दुबई में बैठकर अलग-अलग राज्यों में फैले तंत्र को चला रहा था। पुलिस अब विदेश में बैठे इस सरगना की पहचान करने और उसके नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी है।

जांच में सामने आया है कि आकाश आनंद को जम्मू-कश्मीर में फर्जी बैंक खाते खुलवाने और उनके माध्यम से पैसों का लेनदेन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन खातों में अलग-अलग माध्यमों से रकम पहुंचाई जाती थी। इसके बाद धनराशि को कई अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था, ताकि इसके वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थियों का पता लगाना मुश्किल हो सके। पुलिस को अब तक 70 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के प्रमाण मिले हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसे किन लोगों तक पहुंचाया गया।

पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी इसी तरीके से फर्जी खाते खुलवाए गए थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इस नेटवर्क की गतिविधियों के संकेत मिले हैं। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पुलिस अलग-अलग राज्यों में सक्रिय सदस्यों की पहचान करने के साथ उनके बैंक खातों, सिम कार्ड और वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ रही है।

श्रीनगर के बेमिना में आग का तांडव 80 झोपड़ियां राख; दो की दर्दनाक मौत

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके बेमिना के दुर्बल क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से भारी तबाही मच गई। इस दर्दनाक अग्निकांड में दिल्ली के रहने वाले दो कबाड़ बीनने वालों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि करीब 80 अस्थायी झोपड़ियां और ढांचे जलकर राख हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय मुहम्मद नूर आलम और 16 वर्षीय मुहम्मद अमीन रफी के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली के रहने वाले बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार, आग मंगलवार देर रात अस्थायी झोपड़ियों के एक समूह में लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इन अस्थायी ढांचों में कबाड़ कारोबार से जुड़े लोग रहते थे और अपने कामकाज के लिए भी इनका इस्तेमाल करते थे। झोपड़ियां एक-दूसरे के काफी नजदीक होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। लपटें इतनी भीषण थीं कि लोगों को अपना सामान निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने तक का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

आग से तबाही, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल



आग की चपेट में आने से 80 के करीब अस्थायी ढांचे पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दमकल कर्मियों को आग पर नियंत्रण पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, तब तक आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे में दो लोगों की मौत से प्रभावित बस्ती में शोक का माहौल है। आग से प्रभावित लोगों का घरेलू सामान और आजीविका से जुड़ा सामान भी नष्ट हो गया। कई परिवारों के सामने रहने और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों और संपत्ति को हुए कुल नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है। इस घटना ने अस्थायी बस्तियों में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन बचाव व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नेकां में बगावत तेज, उमर सरकार पर बढ़ा सियासी दबाव



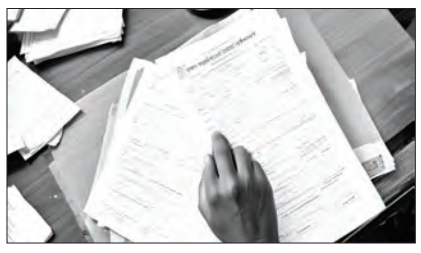
भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) में अंदरूनी असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी, संगठन में महत्वपूर्ण पदों को लेकर असमंजस और सत्ता में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिलने से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों में नाराजगी बढ़ गई है। अब यह असंतोष व्यक्तिगत नाराजगी तक सीमित न रहकर सामूहिक विरोध का रूप लेने लगा है। असंतुष्ट नेताओं ने संगठनात्मक पुनर्गठन के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार को पद से हटाने की मांग उठाई है। इससे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है।

पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता एवं ईदगाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुबारक गुल के तेवर भी चर्चा में हैं। बुधवार को प्रस्तावित प्रेस वार्ता में उनसे उनके अगले राजनीतिक कदम और पार्टी में चल रहे घटनाक्रम को लेकर खुलासे की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

डोगरी भाषा को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगी बिलावर की राधा

भारतेन्दु संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर के बिलावर क्षेत्र के किशनपुर नगरी की रहने वाली राधा देवी भगत ने अपनी उपलब्धि से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्हें डोगरी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति की प्रतिष्ठित पुस्तक परियोजना में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह परियोजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसमें डोगरी सहित देश की करीब 40 भाषाओं को शामिल किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से राधा देवी डोगरी भाषा के समृद्ध मुहावरों, भाषाई विशेषताओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगी। उनके चयन से परिवार के साथ पूरे बिलावर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

फर्जी पीआरसी से एक बेटे को सरकारी नौकरी, दूसरा दो बार बना सरपंच; 13 साल बाद चार्जशीट



भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू। फर्जी स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) बनवाकर सरकारी लाभ हासिल करने के मामले में क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 13 साल की लंबी जांच के बाद चार लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। मामला वर्ष 2013 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी परिवार ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जनगणना रिकॉर्ड और पारिवारिक वंशावली में कथित हेराफेरी कर अपने और परिवार के सदस्यों के पीआरसी बनवाए थे। जांच के अनुसार, सियालकोट निवासी लखन सिंह पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी थे। पंजाब से जम्मू आने के बाद उन्होंने कथित तौर पर गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल कर स्थायी निवासी प्रमाणपत्र हासिल किए। इन प्रमाणपत्रों के आधार पर उनके एक बेटे प्रेम सिंह ने एस्टेट विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, जबकि दूसरे बेटे प्रभाकर सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और दो बार सरपंच निर्वाचित हुआ। आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में जम्मू की एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। मामले की जांच डीएसपी फैसल आरिफ रिशू के नेतृत्व में की गई। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी सुविधाओं और संवैधानिक लाभों का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया गया। 13 साल बाद चार्जशीट दाखिल होने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

उरी फेज-2 टनल प्रोजेक्ट में हादसा, तीन मजदूर घायल

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उरी फेज-द्वितीय टनल प्रोजेक्ट में बुधवार को हुई एक घटना में तीन मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घायल मजदूरों को तत्काल उपचार के लिए बारामुला स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार, तीनों मजदूरों की हालत फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि, घायलों में एक मजदूर को फ्रैक्चर हुआ है, जिसके चलते चिकित्सकों ने उसे सर्जरी कराने की सलाह दी है।

अधिकारियों ने बताया कि घायल मजदूरों की पहचान अब्दुल करीम गनाई और शुकर दीन के रूप में हुई है। दोनों गरकोट के रहने वाले हैं। तीसरे घायल मजदूर की पहचान चीज अहमद मुगल के रूप में हुई है, जो बंदी का निवासी है। घटना के बाद तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। इनमें से एक मजदूर की चोट गंभीर होने के कारण उसकी सर्जरी की तैयारी की जा रही है। हालांकि, उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है। संबंधित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। उरी फेज-द्वितीय टनल परियोजना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों की ओर से घटना के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

आगा रुहुल्ला की नई राजनीतिक पारी की तैयारी

आगा रुहुल्ला अब युवाओं के साथ बनाएंगे अपनी अलग राजनीतिक पहचान

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) से करीब 24 साल पुराना रिश्ता तोड़ने और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नई पारी शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह सक्रिय राजनीति से दूर नहीं होंगे, बल्कि ईमानदार, संवेदनशील और सिद्धांतवादी युवाओं को साथ लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार करने की दिशा में काम करेंगे। हालांकि, उन्होंने अभी तक नई पार्टी बनाने या किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। मंगलवार को बडगाम के बेहिश्त-ए-जेहरा पार्क में अपने पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं बरसी पर आयोजित जनसभा में उन्होंने नेकां से अलग होने का ऐलान किया।



इस दौरान उन्होंने अपने फैसले को इस्तीफा नहीं, बल्कि आजादी बताते हुए कहा, 'यह मेरा इस्तीफा नहीं, आजादीनामा है। आज मैं आजाद हो गया हूं।' उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ईमेल के माध्यम से अपनी सदस्यता छोड़ने का पत्र भी भेजा। मंच पर इस्तीफे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे मोहम्मद अशरफ मट्टू को सौंपना भी उनके राजनीतिक संदेश का हिस्सा रहा।

मट्टू वर्ष 2010 में कथित पुलिस गोलीबारी में मारे गए 17 वर्षीय तुफैल मट्टू के पिता हैं। इस कदम से रुहुल्ला ने नागरिक मौतों और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता देने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं, जिनमें करुणा हो और जो जनता के अधिकारों तथा सम्मान के लिए सिद्धांतों के साथ संघर्ष कर सकें। उनके इस रुख से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है।

बदलाव जनवरी 2027 से बदल जाएगी जम्मू मंडल की चार ट्रेनों की पहचान, लागू होंगे ट्रेनों के नए नंबर

जम्मू-कानपुर एक्सप्रेस बनेगी सुपरफास्ट, गरीब रथ का भी बदलेगा नंबर

भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू

जम्मू संभाग से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर रेलवे ने जम्मू मंडल से संचालित होने वाली चार ट्रेनों के नंबरों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के तहत जम्मू तवी और कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को अब सुपरफास्ट श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू तवी-काठगोदाम के बीच संचालित होने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के नंबर भी बदल दिए जाएंगे। रेलवे की ओर से निर्धारित नई व्यवस्था जनवरी 2027 से अलग-अलग तिथियों पर लागू होगी। इससे जम्मू और आसपास के क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। रेलवे के अनुसार, जम्मू तवी से कानपुर सेंट्रल के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 14670 अब पांच जनवरी 2027 से नए नंबर 12470 के साथ संचालित होगी। इस ट्रेन को जम्मू तवी-कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाएगा। यानी अब यह ट्रेन सुपरफास्ट श्रेणी में अपनी सेवाएं देगी। इसी प्रकार वापसी में कानपुर सेंट्रल से जम्मू तवी आने वाली ट्रेन संख्या 14669 का नंबर भी बदला जाएगा। छह जनवरी 2027 से यह ट्रेन 12469 नंबर के साथ संचालित होगी। इससे दोनों दिशाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान नए नंबर का ध्यान रखना होगा।

◆ टिकट बुकिंग के दौरान नए नंबर का ध्यान रखना होगा

उत्तर रेलवे ने जम्मू तवी और काठगोदाम के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के नंबरों में भी बदलाव किया है। इसके तहत जम्मू तवी से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन संख्या 12208 अब 14696 नंबर से संचालित होगी। यह बदलाव 10 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। वहीं, काठगोदाम से जम्मू तवी आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का नंबर 12207 से बदलकर 14695 कर दिया गया है। वापसी की दिशा में यह नई व्यवस्था 12 जनवरी 2027 से लागू होगी। इस तरह दोनों ट्रेनों के पुराने नंबरों की जगह नए नंबर इस्तेमाल किए जाएंगे। रेलवे के इस फैसले का उद्देश्य परिचालन व्यवस्था में बदलाव के अनुरूप ट्रेनों की पहचान और नंबर प्रणाली को व्यवस्थित करना है।



रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे टिकट आरक्षित करवाने से पहले संबंधित ट्रेन का नया नंबर अवश्य जांच लें। विशेष रूप से जनवरी 2027 में यात्रा करने वाले यात्रियों को पुराने नंबरों के आधार पर जानकारी लेने के बजाय संशोधित नंबरों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार ट्रेन के नंबर में बदलाव होने से यात्रियों को आरक्षण, समय-सारणी और यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में यात्रा से पहले सही जानकारी हासिल करना जरूरी है। यात्री ट्रेनों के नए नंबर, परिचालन और समय-सारणी की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट तथा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके भी जानकारी ली जा सकती है।

स्वाभाविक बड़ा

प्राचीन जल स्रोतों

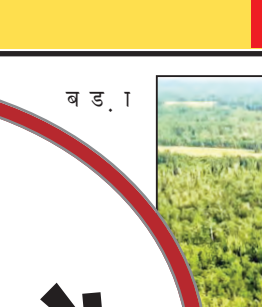
का संरक्षण एवं संवर्धन उच्च मानवीय आदर्श

प्राचीन जल स्रोतों की विलुप्त होती स्थिति आज के समय की एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुकी है। कभी गांवों और कस्बों की जीवनरेखा माने जाने वाले कुएं, बावड़ियां, नाले, धाराएं और झरने न केवल जल की पूर्ति करते थे, बल्कि वे स्थानीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे।

इन जल स्रोतों के इर्द-गिर्द ही सभ्यताओं का विकास हुआ, लोगों की दिनचर्या निर्धारित होती थी और प्राकृतिक संतुलन कायम रहता था। आज जब हम आधुनिकता और विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तब इन्हीं प्राचीन जल स्रोतों का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक भयावह संकेत है।

प्राचीन जल स्रोतों के विलुप्त होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है अनियंत्रित शहरीकरण और अव्यवस्थित विकास। गांवों और कस्बों में बढ़ती आबादी और निर्माण कार्यों ने प्राकृतिक जल स्रोतों को या तो ढक दिया है या उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जहां कभी बावड़ियां और कुएं हुआ करते थे, वहां आज पक्के मकान और सड़कें बन चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या बन गया है। लोग इन स्थानों को अपनी निजी संपत्ति समझकर वहां निर्माण कर लेते हैं, जिससे जल स्रोतों की संरचना नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही, आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जब से नल और ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की उपलब्धता आसान हुई है, तब से लोगों का ध्यान पारंपरिक जल स्रोतों से हट गया है। परिणामस्वरूप इन स्रोतों की देखभाल और संरक्षण की भावना कमजोर पड़ गई है। उपेक्षा के कारण ये स्रोत धीरे-धीरे सूखने लगे और अंतत: समाप्त हो गए।

इसके अलावा, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी जल स्रोतों के सूखने का एक कारण है। पेड़ों की कमी से वर्षा का जल भूमि में समाहित नहीं हो पाता, जिससे भूजल स्तर लगातार गिरता जाता है और जल स्रोत सूख जाते हैं।



सुभाष चंद काशव

जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। अनियमित वर्षा, लंबे सूखे और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी परिस्थितियां प्राकृतिक जल चक्र को प्रभावित करती हैं। इससे जल स्रोतों का पुनर्भरण प्रभावित होता है और वे धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, बढ़ता प्रदूषण भी जल स्रोतों के लिए खतरा बन गया है। नालियों का गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक पदार्थ इन स्रोतों में मिलकर उन्हें दूषित कर देते हैं, जिससे उनका उपयोग असंभव हो जाता है। प्राचीन जल स्रोतों के विलुप्त होने का खमियाजा समाज के हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहला और सीधा प्रभाव जल संकट के रूप में सामने आता है। जब पारंपरिक स्रोत समाप्त हो जाते हैं, तो लोग पूरी तरह आधुनिक जल आपूर्ति पर निर्भर हो जाते हैं, जो हर समय पर्याप्त नहीं होती। गर्मियों के मौसम में जल की कमी विकराल



एआई निर्मित चित्र।

रूप ले लेती है और लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। इससे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर अधिक बोझ पड़ता है। कृषि क्षेत्र भी इससे बुरी तरह प्रभावित होता है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों की आय घटती है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है।

पशुपालन पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। इसके अलावा, जल स्रोतों के समाप्त होने से स्थानीय जैव विविधता भी प्रभावित होती है। कई प्रकार के जीव-जंतु और वनस्पतियां, जो इन स्रोतों पर निर्भर थे, अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। जल की कमी केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट भी उत्पन्न करती है। जब स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता, तो लोगों के बीच विवाद बढ़ते हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। साथ ही, दूषित पानी के उपयोग से डायरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी जलजनित बीमारियां फैलती हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर प्रभावित होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, इन स्रोतों की पहचान और उनका सही दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

हिमालय के सानिध्य में साहित्य और संस्कृति का वैश्विक संगम

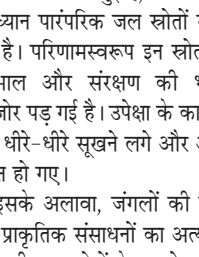
हिमालय केवल पर्वतों की शृंखला नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, प्राकृतिक संपदा और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत प्रतीक है। इसकी ऊँची चोटियाँ मनुष्य को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती हैं, जबकि इसकी नदियाँ जीवन और सभ्यताओं के विकास का संदेश देती हैं। इसी हिमालयी चेतना को साहित्य, कला, संस्कृति और वैश्विक संवाद से जोड़ने वाला तृतीय अंतरराष्ट्रीय 'स्पर्श पर हिमालय' 2026 महोत्सव उत्तराखंड के देहरादून स्थित लेखक गाँव, थानो में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न देशों और भारत के अनेक राज्यों से आए साहित्यकारों, कलाकारों, विद्वानों तथा रचनात्मक व्यक्तियों ने भाग लेकर विचारों और अनुभवों को साझा किया।

आज विश्व राजनीतिक तनाव, युद्ध, सांस्कृतिक टकराव, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विभाजन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में साहित्य और संस्कृति की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति जहाँ देशों और समाजों के बीच सीमाएँ खड़ी करती है, वहीं साहित्य प्रेम, करुणा, शांति, न्याय और मानवीय गरिमा जैसे साझा मूल्यों के माध्यम से लोगों को जोड़ता है। भाषाएँ और जीवनशैली भले ही अलग हों, लेकिन मानवीय संवेदनाएँ सभी में समान होती हैं। साहित्य इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्ति देकर वैश्विक एकता का मार्ग प्रशस्त करता है।

'स्पर्श पर हिमालय' जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन विभिन्न देशों और भारतीय राज्यों के रचनाकारों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजन केवल औपचारिक चर्चाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विभिन्न समाजों की परंपराओं, ऐतिहासिक अनुभवों, साहित्यिक प्रवृत्तियों और समकालीन चुनौतियों को समझने का माध्यम बनते हैं। इस आयोजन का स्थल लेखक गाँव भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण परिवेश में साहित्यिक गतिविधियों का विस्तार इस धारणा को बदलता है कि रचनात्मकता और बौद्धिक विमर्श केवल महानगरों तथा बड़े सभागारों तक



एआई निर्मित चित्र।



(डॉ. सत्यवान सौरभ

सीमित हैं। गाँव हमारी लोकभाषाओं, लोककलाओं, परंपराओं और जीवनानुभवों के प्रमुख स्रोत रहे हैं।

लेखक गाँव केवल कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान नहीं, बल्कि लेखन, चिंतन, अनुसंधान, अनुवाद और सांस्कृतिक संवाद का जीवंत केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रकृति के समीप रहकर लेखक अपनी रचनात्मक ऊर्जा को नई दिशा दे सकते हैं। हिमालय की शांति, विविधता और गहराई रचनाकारों को समाज और मानवीय जीवन के विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय साहित्य की शक्ति भी उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में निहित है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गढ़वाली और कुमाऊँनी सहित विभिन्न भाषाएँ अपने समाज की स्मृतियों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती हैं। ऐसे मंच इनके बीच संवाद और अनुवाद को बढ़ावा दे सकते हैं।

साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को संवेदनशील बनाना और समय की चुनौतियों से परिचित कराना भी है। बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, जातिगत विषमता, उपभोक्तावाद और पर्यावरणीय संकट जैसे विषयों पर साहित्यकार अपनी लेखनी से जनचेतना विकसित कर सकते हैं। जब साहित्य किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं की आवाज बनता है, तब वह सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए लेखक गाँव जैसे केंद्रों पर केवल साहित्यिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोहों के बजाय पुस्तकों के प्रकाशन, अनुवाद परियोजनाओं, शोध संवादों और युवा लेखकों के प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

हणोगी माता मंदिर: आस्था, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम

बर्फ से लकदक हिमालय की गोद के बीच अवस्थित हिमाचल प्रदेश देवभूमि वास्तव में किसी तराशे हुए हीरे से कम नहीं है। अपार प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व यहां के कुदरती नैसर्गिक के गौरव को आज भी बरकरार रखे हुए है। यहां के स्थानीय लोगों को ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा में समर्पित हुए अक्सर देखा जा सकता है। कहा जाता है कि देवी-देवता मनुष्य की तीन रूपों में सेवा करते हैं, जोकि धार्मिक रूप में, मानसिक व आध्यात्मिक शांति देकर, इच्छापूरक के रूप में सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर और रक्षक के रूप में जादू टोना, भूत-प्रेतों और अन्य प्रकृतिक या अप्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करते हैं। इसी कड़ी में इस राज्य के जनपद मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के मध्य और पंडोह बांध के नजदीक अवस्थित तथा ब्यास नदी की तलहटी के उस पार हणोगी माता का अलौकिक मंदिर की दिव्यता तो देखते ही बनती है। हणोगी माता मंदिर के इर्द-गिर्द जैसे कुदरत ने अपने सौंदर्य का अनुपम थाल यहीं परोस दिया हो, जिसका वर्णन शायद शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कुल्लू वैसे भी अनेक देवी-देवताओं व ऋषि-मुनियों की तपोस्थली रही है और वह किसी न किसी ऐतिहासिक किंवदंतियों तथा जनश्रुति से जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, कई महात्माओं ने यहां अपनी घोर तपस्या के द्वारा अनेक सिद्धियां को प्राप्त किया हुआ है। देवी पूजा का पहाड़ों में ही नहीं बल्कि हमारे समस्त देश में इसका प्रचलन सदियो से चला आ रहा है। कहते हैं कि देवी या शक्ति ही सृष्टि के मूल में निहित है। कुल्लू-



एआई निर्मित चित्र।

प्राचीन गुफा में विराजमान मां तुंगा की दिव्य प्रतिमा

मंडी के मध्य हणोगी नामक स्थान पर स्थित माता हणोगी अपने तीन रूपों में विराजमान है। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में इस जगह पर अभय राम गुरु रहा करते थे,जो देवी हणोगी मां के प्रति भक्ति में सदा समर्पित रहते थे। जनश्रुति अनुसार वह तांत्रिक विद्या में काफी पारंगत थे तथा अपनी शक्तियों के माध्यम से तुंगधारा पर्वत श्रृंखला से तुंगा माता को हणोगी में लेकर आए थे और कई वर्षों तक इस देवी की पूजा-अर्चना करते रहे। यह देवी 'तुंगाधार की जोगणी' के नाम से भी प्रचलित है। तुंगा मां की पांच हजार वर्ष पुरानी कलात्मक और अलौकिक पाषाण मूर्ति, जो पुरातन गुफा में विद्यमान है, प्रत्येक आगंतुक को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेती है। हणोगी में ही काली माता का पुरातन भव्य मंदिर भी है,जो आज भी भक्तों की श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। जब तक गुरु अभय राम थे तो उन्होंने माता की पूजा- अर्चना को प्रतिदिन निर्बाध जारी रखा। उनके मरणोपरांत मां की पूजा करने वाला कोई नहीं था। फलस्वरूप जिसके इस स्थल के इर्द-गिर्द आए-दिन कई अनहोनी घटनाएं घटित होने लगी। हणोगी माता मंदिर से जुड़ी दंतकथाएं स्थानीय लोगों की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाती हैं।



तुलसी राम डोगरा

कहा जाता है कि गुरु अभय राम के निधन के बाद देवी की पूजा-अर्चना बंद हो गई, जिसके कारण क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं होने लगीं। लोगों ने इसे देवी का प्रकोप माना। एक अन्य कथा के अनुसार, एक श्रद्धालु को स्वप्न में देवी ने दर्शन देकर अपने स्थान की उपेक्षा न करने का संदेश दिया। इसके बाद वटवृक्ष को देवी स्वरूप मानकर पूजा आरंभ की गई। बाद में देवी के आदेशानुसार मंदिर निर्माण करवाया गया और दुर्घटनाएं कम हो गईं। वर्तमान में हणोगी में मां काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीन रूपों में विराजमान हैं। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं को शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। यहां नवरात्र में विशाल आयोजन, लंगर, कन्या-विवाह, चिकित्सा सुविधा और संस्कृत महाविद्यालय जैसे सामाजिक कार्य भी संचालित होते हैं। रोप-वे और व्यास नदी के मनोरम दृश्य इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ाते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सुपर अल नीनो की आहट, दुनिया के मौसम पर संकट के बादल



एआई निर्मित चित्र।

जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से गर्म होना दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों की चिंता बढ़ा रहा है। अल नीनो की मौजूदा घटना के मजबूत होने और दिसंबर के आसपास चरम पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसे संभावित रूप से 'सुपर अल नीनो' की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता है। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी, बारिश और सूखे की परिस्थितियों पर पड़ सकता है, जिससे मानव जीवन और पर्यावरण के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन संस्था (एनओएए) के आंकड़े भी प्रशांत महासागर में बढ़ती गर्मी की ओर संकेत करते हैं। 22 अक्टूबर के आकलन के मुताबिक, मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। जून में यह तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो अगस्त में बढ़कर 2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि अल नीनो क्या है और इसे लेकर चिंता क्यों बढ़ रही है।

अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र का समुद्री पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इससे समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाओं, बादलों और वर्षा की गतिविधियों में बदलाव आता है। इसका प्रभाव प्रशांत महासागर से दूर स्थित देशों के मौसम पर भी पड़ सकता है। कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ सकती है, तो कहीं बारिश की मात्रा में कमी या असामान्य वर्षा देखने को मिल सकती है।

भारत के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल नीनो का असर मानसून पर पड़ सकता है। हालांकि, प्रत्येक अल नीनो वर्ष में भारत में सूखा पड़े, यह जरूरी नहीं है। देश में मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम रहने की बात सामने आई है। डब्ल्यूएमओ के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। पहले से बढ़ते वैश्विक तापमान के बीच प्रशांत महासागर का गर्म होना मौसम संबंधी चुनौतियों को और गंभीर बना सकता है।



वीरेन ठाकुर

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें भी पर्यावरण और ओजोन परत को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कहीं सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है, तो कहीं बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जानमाल का भारी नुकसान करती हैं। ऐसे में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करने के बदले हम प्रकृति को क्या लौटा रहे हैं?

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

कविता

लोकतंत्र एक 'नारा'

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

कभी व्यवस्था पर है प्रश्न उठाते,
कभी संविधान की बात सुनाते।
लेकिन जब
'अवसर' मिलता है,
वे तभी वादों को भूल भी जाते।
अब सत्ता पक्ष को भी ध्यान रहे,
अहंकार की कोई सीमा होती है।
जनता जब कभी करवट लेती है,
तब हरेक
कुर्सी हिलती रहती है।
लोकतंत्र केवल एक 'नारा' नहीं,
ये जनता का परम् अधिकार है।
वह सत्ताधारी हो या विपक्ष यहाँ,
इन सभी का एक ही आधार है।
रोटी जले तो तुरंत
'आँच' बदलो,
नहीं है चूल्हा बदलने की जरूरत।
भोली-भाली जनता को सपने नहीं,
काम व विकास दिखाओ झटपट।
क्योंकि लोकतंत्र में आखिरकार,
जन-जन की
ही होती सरकार है,
कुर्सी आती-जाती रहती हरबार,
यहाँ जनता ही असली दरबार है!

संपादकीय

खुशियों पर प्रदूषण का साया

हरित पटाखों के इस्तेमाल और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की सीमित छूट देने के 24 घंटे बाद ही राजधानी में पारंपरिक पटाखों की खुलेआम बिक्री का मामला सामने आना चिंताजनक है। इस पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए सरकार को अपने निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में कितने प्रभावी कदम उठाते हैं। पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद पटाखा विक्रेता किसी न किसी तरीके से प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करने में सफल हो जाते हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि हरित पटाखों की आड़ में पारंपरिक पटाखों की बिक्री भी होती रहती है। ये पटाखे वातावरण में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके बावजूद बाजार में इनकी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं बन पाई है। कई बार पटाखा विक्रेता हरित पटाखों के नाम पर सामान्य पटाखे बेच देते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बाजार में केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले हरित पटाखे ही उपलब्ध हों। इसके लिए प्रशासन को बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

पटाखों के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों में जिम्मेदारी और संयम की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। आम तौर पर दीपावली के अवसर पर निर्धारित समयसीमा की अनदेखी करते हुए देर रात तक पटाखे चलाए जाते हैं। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि पटाखों के धुएं से हवा की गुणवत्ता खराब होती है। पिछले कुछ वर्षों में दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। हवा में मौजूद हानिकारक कण सांस संबंधी परेशानियां बढ़ाते हैं और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से परेशानी पैदा करते हैं।

यह सही है कि दीपावली पर पटाखे चलाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और बहुत से लोग इसे त्योहार के उल्लास का हिस्सा मानते हैं। लेकिन परंपरा का निर्वहन करते समय दूसरों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता करना भी जरूरी है। त्योहार की खुशियां मनाने के लिए पटाखों का असीमित इस्तेमाल आवश्यक नहीं है। लोग अपनी गली, मोहल्ले और आवासीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से किसी खुले स्थान पर सीमित समय के लिए पटाखे चला सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि केवल प्रमाणित हरित पटाखों का ही इस्तेमाल हो। इस तरह त्योहार का उत्साह भी बना रहेगा और प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में भी मदद मिलेगी।

पिछले दो-तीन दशकों में वायु प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सर्दियों के आगमन के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। दीपावली के आसपास प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ने से स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। हालांकि, वायु प्रदूषण के लिए केवल पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली और कूड़ा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल तथा औद्योगिक गतिविधियां भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद पटाखों के इस्तेमाल को लेकर लापरवाही बरतना समस्या को और गंभीर बनाता है।

इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाएं अक्सर तब सक्रिय होती दिखाई देती हैं, जब हालात गंभीर हो जाते हैं। पहले से प्रभावी कदम उठाने के बजाय कई बार केवल औपचारिक कार्रवाई तक ही सीमित रहा जाता है। पटाखों की बिक्री पर निगरानी, निर्धारित समयसीमा का पालन, हरित पटाखों की पहचान और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जैसे उपाय लगातार किए जाने चाहिए। केवल आदेश जारी करने से प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

वायु प्रदूषण का संकट किसी एक दिन या एक त्योहार तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी तंत्र और आम जनता, दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लोगों को भी यह महसूस करना होगा कि मनमाने ढंग से पटाखे चलाना केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं, बल्कि दूसरों की सेहत से जुड़ा मामला है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में शासन-प्रशासन को नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा और नागरिकों को भी प्रदूषण रोकने के प्रयासों में सहयोग देना होगा। तभी दीपावली की खुशियां पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए संकट बने बिना मनाई जा सकेंगी।

-शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

जिसका नाम भी विराट और काम भी विराट

विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव क्रिकेट की ओर था। महज तीन साल की उम्र में उन्होंने बल्ला थाम लिया था और अपने पिता से गेंदबाजी करने के लिए कहते थे। परिवार के अनुसार, छोटी उम्र में ही क्रिकेट के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देने लगा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाल भारती पब्लिक स्कूल में हुई। उनका बचपन दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीता। क्रिकेट में उनकी प्रतिभा को देखते हुए परिवार और आसपास के लोगों ने उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण दिलाने की सलाह दी।



विराट कोहली
जन्म : 5 नवंबर 1988

वर्ष 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी की स्थापना हुई। इसी दौरान विराट के पिता प्रेमनाथ कोहली ने उन्हें क्रिकेट प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा से मिलवाया। राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में विराट ने क्रिकेट की बारीकियां सीखनी शुरू कीं। शुरुआत में वह गली क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए परिवार ने उन्हें नियमित प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अकादमी में अभ्यास करना शुरू किया और सुमीत डोगरा अकादमी में भी मैच खेले।

विराट कोहली का शुरुआती क्रिकेट सफर आसान नहीं रहा। उन्हें दिल्ली की अंडर-14 टीम में जगह नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि उनके पिता के सामने प्रभावशाली क्लबों के माध्यम से चयन कराने के प्रस्ताव भी आए, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। प्रेमनाथ कोहली चाहते थे कि उनके बेटे को उसकी प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर ही अवसर मिले। बाद में विराट को दिल्ली की अंडर-15 टीम में जगह मिली। क्रिकेट को गंभीरता से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नौवीं कक्षा में अपना स्कूल बदलकर सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला लिया। 18 दिसंबर 2006 को विराट के जीवन में बड़ा दुखद मोड़ आया। उनके पिता प्रेमनाथ कोहली का मस्तिष्काघात के कारण निधन हो गया। पिता के निधन का उन पर गहरा असर पड़ा। परिवार के अनुसार, इस घटना के बाद उनके व्यवहार और सोच में बदलाव आया। उन्होंने क्रिकेट को पहले से अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। पिता का सपना और उनका मार्गदर्शन विराट के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

जब भी जनता कांग्रेस को नकारती है, वह निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाती है: डॉ बिंदल

प्रदेश सरकार कर रही वादाखिलाफी, राज्य में पैदा कर रही अराजकता का माहौल: अनुराग ठाकुर





सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बुधवार को भाजपा द्वारा लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के अंतर्गत पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। यह पदयात्रा हमीरपुर बाईपास स्थित नीजी पैलेस से शुरू हुई। वहां से होते हुए यह भोटा चौक पहुंची और अंत में गांधी चौक पर जाकर संपन्न हुई। पूरी पदयात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।

शीर्ष नेताओं की रही गरिमामयी मौजूदगी: इस अभियान और पदयात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल और हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ ही विधायक आशीष शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कई अन्य वर्तमान व पूर्व विधायक और पदाधिकारी भी इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बने।

कांग्रेस की कथित नकारात्मक राजनीति पर बोला हमला: पदयात्रा से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और उसकी राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हताशा में देश की संवैधानिक संस्थाओं, जैसे चुनाव आयोग और ईवीएम पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने का कुचक्र रच रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि जब भी जनता कांग्रेस को नकारती है, वह निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर भारत की लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ कांग्रेस को सत्ता सौंपी थीए सरकार उन पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने प्रदेश सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल को महिला विरोधी नीतियोंए भ्रष्टाचार के आरोपों और जनविरोधी फैसलों से घिरा हुआ बताया। वहीं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादाखिलाफ करने और राज्य में अराजकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी पराजय को स्वीकार करने के बजाय लगातार संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर देश में भ्रम और अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार और केरल सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं। यदि ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठा रही हैए तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चुनाव परिणामों के आधार पर केरल के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देंगेघ् कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उसके आरोप सही हैं या फिर कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों का चुनावी जनादेश।

जनता को जागरूक करने का संकल्प: भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की मजबूती और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए पार्टी का यह जनजागरण अभियान अब प्रदेश के कोने.कोने तक पहुंचेगा। इस रैली ने साफ कर दिया है कि भाजपा आने वाले समय में राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर अपने आंदोलन को और उग्र करने जा रही है।

इस अवसर पर बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जंवाल सहित हमीरपुर लोकसभा के सभी विधायक एवं पूर्व विधायक सहित जिलाध्यक्ष एवं सभी मंडलों के मंडलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क तेज करने और प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए अपना अभियान लगातार जारी रखेगी।

संविधान और अधिकारों की रक्षा के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठें समाज के सभी वर्ग



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेशस्तरीय बैठक बुधवार को बिलासपुर के लखनपुर स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के बिलासपुर जिला प्रधान एवं सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल ने की।

इसमें शिमला, कुल्लू, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना सहित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। राजनीतिक दल नहीं चाहते कि समाज के विभिन्न वर्ग एक मंच पर आएं। इसलिए लोगों को ऐसी साजिशों से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा आज सबसे बड़ी चुनौती है। संशोधन के नाम पर संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ का असर शोषित और वंचित वर्गों पर पड़ सकता है। प्रदेश प्रधान महासचिव ताराचंद रणौट ने कहा कि आरक्षण का लाभ पात्र लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा और एट्रोसिटी एक्ट के मामले भी प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डॉ. विनिश चौधरी ने यूजीसी के समानता संबंधी नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, दिव्यांगता, लिंग और आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है।

लंबित बिजली बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें उपभोक्ता : निशांत शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। लक्ष्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसे सरकाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत चोलथरा के दीघो गांव के दो सगे भाइयों ने अपनी उपलब्धि से साबित किया है। मेजर प्रशांत सिंह और उनके छोटे भाई मेजर प्रभात सिंह ने भारतीय सेना में मेजर के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचकर परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

विशेष बात यह है कि छोटे भाई प्रभात सिंह को इसी सप्ताह पदोन्नति मिली है। इसके बाद दोनों भाई सेना में मेजर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में मेजर प्रभात सिंह जम्मू-कश्मीर और मेजर प्रशांत सिंह राजस्थान में तैनात हैं। प्रशांत सिंह आर्टिलरी रेजिमेंट और प्रभात सिंह एयर डिफेंस रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। दोनों भाई ऑपरेशन सिंदूर सहित सेना के महत्वपूर्ण अभियानों का हिस्सा भी रहे हैं। दोनों भाइयों की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में हुई। इसके बाद प्रशांत ने यूपीईएस देहरादून से कानून की शिक्षा प्राप्त की, जबकि प्रभात ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद दोनों ने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं शुरू कीं। उनकी सफलता में माता-पिता के संस्कार और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिता परजीत सिंह ठाकुर शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता रंजना ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोलथरा में टीजीटी नॉन मेडिकल हैं। दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत और लगन से सेना में यह मुकाम हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर ग्राम पंचायत प्रधान विजय बनयाल, उपप्रधान राकेश बनयाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई।



न्यूज ब्रीफ

दिव्यांग बच्चों के बनाए उत्पादों को दीपावली प्रदर्शनी में मिला शानदार प्रतिसाद

भारतेन्दु संवादाता, बिलासपुर। चेतना संस्था के दिव्यांग बच्चों की ओर से दीपावली के अवसर पर तैयार किए गए उत्पादों की विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शनी लगाई गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान बच्चों ने मोमबत्तियां, मिट्टी के दीपक, बंधन द्वार सहित कई आकर्षक वस्तुएं तैयार की थीं। इन उत्पादों की प्रदर्शनी स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंदरौर, हिम सर्वोदय स्कूल घुमारवीं, शिवा इंटरनेशनल स्कूल घुमारवीं, डीएवी पब्लिक स्कूल बरमाणा व बिलासपुर सहित कई संस्थानों में लगाई गई। प्रदर्शनी में करीब छह हजार विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक खरीदारी की। इस पहल से दिव्यांग बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन मिला और उनके हुनर को पहचान मिली।

विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ जातिगत भेदभाव एवं दुर्व्यवहार की घटनाएं चिंताजनक: अभाविप

भारतेन्दु संवाददाता, चंबा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रांत मंत्री कुमारी नैंसी अटल ने चंबा जिले के सामरा विद्यालय में छात्रा के साथ कथित जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में कार्यरत एक मल्टीटास्क महिला कर्मचारी पर बच्ची को शौचालय में बंद करने का आरोप है। कर्मचारी पर महिला अध्यापिका के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप भी सामने आए हैं। नैंसी अटल ने कहा कि विद्यालय में हर विद्यार्थी को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। अभाविप ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

विकसित भारत युवा संवाद में 200 युवाओं ने लोकतंत्र के प्रति जताई प्रतिबद्धता

भारतेन्दु संवाददाता, पांवटा साहिब। मेरा युवा भारत, सिरमौर की ओर से ग्लोबल अकादमी पब्लिक स्कूल में विकसित भारत युवा संवाद आयोजित किया गया। इसमें करीब 200 युवाओं ने भाग लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। सांसद सुरेश कश्यप और विधायक सुखराम चौधरी ने युवाओं के सवालों के जवाब दिए। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर और युवा आइकन कनिष्क शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन लोकतांत्रिक शपथ के साथ हुआ। इसी दौरान 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर जिला स्तरीय युवा संसद भी हुई, जिसमें 50 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रियांजलि शर्मा प्रथम, शिवम द्वितीय और सना तृतीय रहे।

पिज़्ज़ा-बर्गर छोड़िए, बच्चों की सेहत का असली खजाना तो हिमाचल की रसोई में ही छिपा है!

सन्नी महाजन, भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। धर्मशाला के बाल हार्मोन विशेषज्ञ डॉ. अतुल गुप्ता ने बच्चों के बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पारंपरिक हिमाचली खानपान अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड के बजाय बच्चों को राजमा, कुल्थ की दाल, सिड्डू, मदरा, बबरू और मोटे अनाज खिलाने चाहिए। स्थानीय दालें, दूध, दही, पनीर, मौसमी फल और अखरोट संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने भोजन में अधिक तेल, घी और नमक से बचने की सलाह दी। बच्चों की लंबाई या वजन सामान्य रूप से न बढ़ने पर चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए।

बीड़ में बड़े यात्री और पर्यटक बसों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने बैजनाथ उपमंडल के बीड़ में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी यात्री एवं पर्यटक बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार, चौगान चौक से तिब्बती मार्केट बीड़ की ओर जाने वाली सड़क पर वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज-बेंज, लग्जरी कोच और स्लीपर कोच सहित बड़ी बसों का प्रवेश सुबह आठ बजे से शाम साढ़े सात बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि संकरी सड़क पर बसों से यातायात बाधित होता है और पर्यटकों, स्थानीय लोगों तथा पैराग्लाइडिंग पायलटों को परेशानी होती है। एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी।

एंटी चिट्टा अभियान के तहत नूरपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 48.30 लाख की संपत्ति जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल में पहली बार जब्त मकान का वास्तविक कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त कर उसे सील किया है। यह कार्रवाई पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। पुलिस ने डमटाल निवासी शमशेर सिंह की छन्नी स्थित दो मंजिला आवासीय इमारत को कब्जे में लिया है। भवन का मूल्य 45.90 लाख रुपये आंका गया है। इसके साथ 2.40 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। कुल जब्त संपत्ति की कीमत 48.30 लाख रुपये है।

पालमपुर में चिट्टा तस्करों के हौसले बुलंद आखिर किसके संरक्षण में चल रहा नशे का कारोबार? : त्रिलोक कपूर

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने पालमपुर में बढ़ते चिट्टे के कारोबार पर कांग्रेस सरकार और स्थानीय प्रशासन को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद विंढ्रावन की अस्थायी पुलिस चौकी क्यों हटाई गई और इसके पीछे किसका दबाव था। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्य बाजार की एक हैंडलूम दुकान में कोरियर से आए सामान में 10.41 ग्राम चिट्टा बरामद होना चिंताजनक है। कपूर ने नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क और मुख्य सरगनाओं की जांच की मांग की। उन्होंने विंढ्रावन पुलिस चौकी दोबारा स्थापित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई राजनीति से ऊपर उठकर लड़नी होगी। सरकार को चुप्पी तोड़कर जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए।

खेलो हिमाचल अभियान से युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल: यादविंदर गोमा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेलों से जोड़ने और चिट्टा सहित अन्य नशों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान-2026' आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा की अध्यक्षता में बैठक हुई। गोमा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार पहली बार प्रदेश में खेलो इंडिया की तर्ज पर व्यापक खेल आयोजन किया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 20 नवंबर को एचपीसीए मैदान में होगा। इस दौरान ड्रोन शो, लेजर शो और सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी। अभियान के तहत 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए छह खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। इनका आयोजन उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

केरल के एमएसडब्ल्यू विद्यार्थियों ने कुल्लू में सामाजिक सेवा संस्थानों का किया शैक्षणिक भ्रमण

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम (केरल) के मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) के विद्यार्थियों ने सांफिया फाउंडेशन और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में फाउंडेशन की ओर से संचालित जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) का शैक्षणिक भ्रमण किया। यह भ्रमण विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के तहत आयोजित राष्ट्रीय अवलोकन भ्रमण का हिस्सा था। इस दौरान विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग के सहायक प्राध्यापक हरिशंकर एमपी और शॉनली केजी भी विद्यार्थियों के साथ मौजूद रहे।

भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों से परिचित कराना था। इससे उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने का अवसर मिला।



◆ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की पहल से रूबरू हुए विद्यार्थी

सांफिया फाउंडेशन की क्लिनिकल प्रमुख डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज ने विद्यार्थियों को केंद्र की कार्यप्रणाली और विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों में विकासात्मक विलंब एवं दिव्यांगता की समय रहते पहचान, प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा उनके सर्वांगीण विकास में उपचारात्मक सेवाओं और थैरेपी के महत्व को समझाया। वहीं, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र कुल्लू की प्रभारी डॉ. रेखा ठाकुर ने स्वास्थ्य एवं पुनर्वास के क्षेत्र में सामाजिक कार्य की भूमिका, लाभार्थियों और उनके परिवारों को मिलने वाली सहायता तथा सामाजिक समावेशन के महत्व पर प्रकाश डाला।

विद्यार्थियों को सांफिया फाउंडेशन की पहल 'दिव्यांग मित्र केंद्र' के कार्यों से भी अवगत करवाया गया। इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके परिवारों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पेंशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग दिया जाता है।

ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए अजय वर्मा ने उठाए कदम

◆ कोहाला में सोलर लाइटें और हैंडपंप लगाने का आश्वासन

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। कोहाला पंचायत की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने बुधवार को कांगड़ा स्थित कार्यालय में एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान पंचायत के उपप्रधान रविन्द्र सिंह और अन्य सदस्यों ने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखीं।

अजय वर्मा ने पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में दो सोलर लाइटें लगवाने, कोहाला से कांगड़ा के लिए बस सेवा शुरू करवाने तथा एक हैंडपंप स्थापित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। गांवों में सड़क, परिवहन, पेयजल और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।



अजय वर्मा ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंचायत की ओर से उठाई गई मांगों पर गंभीरता से काम किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इससे पंचायत क्षेत्र में परिवहन, पेयजल और रोशनी की सुविधा बेहतर होगी तथा ग्रामीणों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिलेगी।

शिक्षा सुधार के लिए सरकार की योजनाओं का दिखने लगा असर: केवल सिंह पठानिया

शिक्षा रैंकिंग में हिमाचल पांचवें स्थान पर पहुंचा

भारतेन्दु संवाददाता, शाहपुर। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मंगलवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है।

इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर इन स्कूलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।



उन्होंने बताया कि इन स्कूलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी प्रतिभा को निखारने के बेहतर अवसर देना है। पठानिया ने कहा कि स्कूलों में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है, ताकि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। सरकार का लक्ष्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर विधायक ने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत भी की।

घेराबंदी जयराम ठाकुर बोले, चुनावी हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही कांग्रेस

मुख्यमंत्री सुक्खू को चुनाव आयोग पर संदेह है तो दें तत्काल इस्तीफा: जयराम ठाकुर

रूप लाल कौंडल, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। पड्डल मैदान से शुरू हुई पदयात्रा सेरी मंच पहुंचकर जनसभा में बदल गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पदयात्रा का नेतृत्व किया और कांग्रेस तथा विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंडी में उमड़ा जनसमर्थन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जनता की एकजुटता दर्शाता है।

जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश विकास, सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार, चुनाव में हार मिलने पर कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है और 'वोट चोरी' जैसे आरोपों के जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है।



उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस प्रचार का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के लिए अराजकता का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी परिवार की धमकियों से नहीं। एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य गलत वोट बनने से रोकना और सही मतदाताओं के नाम सूची से नहीं कटने देना है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर इसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भी इसी चुनाव प्रक्रिया से संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। यदि उन्हें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने रामपुर के विधायक की मृत्यु के दिन मुख्यमंत्री के चंबा में कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी आलोचना की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्य ठप होने और चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार नई घोषणाएं कर रही है, जबकि पुरानी गारंटियां अधूरी हैं। उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए सरकार के आर्थिक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने मंडी की सभी दस सीटों पर भाजपा की जीत और प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया। जयराम ठाकुर ने कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज का जवाब देगी। जनसभा में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक एवं रैली संयोजक राकेश जम्वाल सहित भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

रैली के चलते वाहनों के पहिए थमे: भाजपा की पदयात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक पहुंचाने के लिए रामनगर में प्रताप पैलेस के पास और अस्पताल रोड पर विजय हाई स्कूल के निकट कुछ समय के लिए वाहनों को रोका गया। इस पर कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि कार्यकर्ता सड़क किनारे दो-दो की कतारों में भी सभा स्थल तक जा सकते थे। इससे यातायात बाधित नहीं होता और आम लोगों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

देहरा परिसर के निर्माण को मिली 50 करोड़ की संजीवनी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) के देहरा स्थित स्थायी परिसर के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए कुलपति ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर लंबित कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। विश्वविद्यालय को परिसर के निर्माण एवं विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह राशि आगामी निर्माण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दी गई है। कुलपति ने विभाग को पर्याप्त कर्मचारी, मशीनरी और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाकर कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही प्रत्येक भवन के निर्माण की समयसीमा तय करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिसर में बिजली और जलापूर्ति संबंधी आधारभूत ढांचे के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। विश्वविद्यालय अप्रैल 2027 तक शैक्षणिक गतिविधियां देहरा परिसर में स्थानांतरित करने के लिए प्रयासरत है।

पानीपत के कारोबारी से 40 लाख की फिरौती मांगी

◆ विदेशी नंबर से कॉल कर व्यापारी को जान से मारने की धमकी

भारतेन्दु संवादाता, पानीपत। जिले के मतलौडा अड्डे पर किराणा की दुकान चलाने वाले एक कारोबारी से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। विदेशी नंबर से आई कॉल में व्यापारी को रकम देने के लिए 7 नवंबर तक का समय दिया गया है। पैसे नहीं देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। घटना के बाद व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है।

जानकारी के अनुसार, मतलौडा अड्डे पर बजाज किराणा स्टोर चलाने वाले अमरदीप बजाज उर्फ शेरू के पास मंगलवार सुबह एक विदेशी नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को काला जठेड़ी और लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा बताया। उसने व्यापारी से 40 लाख रुपये की मांग की। साथ ही स्पष्ट किया कि 7 नवंबर तक रकम का इंतजाम कर दिया जाए। तय समय तक पैसे नहीं मिलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। अचानक आई इस धमकी भरी कॉल से व्यापारी घबरा गया। उसने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार में चिंता का माहौल बन गया। इसके बाद अमरदीप बजाज ने मतलौडा थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापारी अन्य लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण से भी मिला। उसने एसपी के समक्ष अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। हालांकि, सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद व्यापारी के अकेले बाइक पर घूमने की तस्वीर भी सामने आई है। फिरौती की मांग और धमकी के बाद इलाके के व्यापारियों में भी चिंता बनी हुई है।

फिरौती की धमकी से मतलौडा के व्यापारियों में दहशत

व्यापारी ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विदेशी नंबर से आई कॉल के बाद से परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर चिंतित हैं। वहीं, फिरौती की मांग सामने आने के बाद मतलौडा क्षेत्र के अन्य दुकानदारों में भी डर का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों से कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। पुलिस की ओर से व्यापारी की सुरक्षा के लिए दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अब व्यापारी और उसके परिजनों को पुलिस जांच तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है।

हरियाणा की 629 गोशालाओं को 86.95 करोड़ की मदद

दीपावली पर मिट्टी के दीये और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की मुख्यमंत्री ने की अपील

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गोवंश संरक्षण और गोशालाओं के विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से राज्य की 629 गोशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी की गई है। इस राशि का उपयोग गोशालाओं में गोवंश की बेहतर देखभाल, चारे की व्यवस्था, शेड निर्माण, रखरखाव और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण और उनकी बेहतर देखभाल के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोशालाओं को आर्थिक रूप से



मजबूत बनाने के साथ वहां उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की 629 गोशालाओं के लिए करोड़ों रुपये की राशि जारी की गई है। इससे गोशालाओं में रहने वाले गोवंश के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से जारी 86.95 करोड़ रुपये की राशि गोशालाओं की विभिन्न आवश्यकताओं पर खर्च की जाएगी। इसमें गोवंश के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना, शेड का निर्माण करवाना और पहले से उपलब्ध सुविधाओं का रखरखाव शामिल है।

वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने की अपील

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के अवसर पर लोगों को मिट्टी के दीये जलाने चाहिए और स्थानीय दुकानदारों तथा कारीगरों से सामान खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पादों को खरीदने से छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिलती है। इससे स्थानीय बाजारों में कारोबार को बढ़ावा मिलता है और पारंपरिक कामों से जुड़े लोगों को भी लाभ पहुंचता है।

गोशालाओं में पशुओं को सुरक्षित रखने और उनकी नियमित देखभाल के लिए बुनियादी सुविधाओं का होना जरूरी है। आर्थिक सहायता मिलने से गोशाला संचालकों को इन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में गोशालाएं गोवंश के संरक्षण और देखभाल का कार्य कर रही हैं। ऐसे में उनके संचालन और रखरखाव के लिए आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से जारी यह राशि गोशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण को लेकर गंभीर है। गोशालाओं को सहायता उपलब्ध करवाने का उद्देश्य वहां रहने वाले पशुओं को बेहतर सुविधाएं देना और उनके रखरखाव में सहयोग करना है।

हरियाणा में दीपावली पर चिकित्सा सेवाओं की तैयारी, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश

सरकारी अस्पतालों में 20 से अधिक बेड आरक्षित रखने के निर्देश

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा में दीपावली के दौरान संभावित हादसों और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को बर्न वार्ड तैयार रखने और आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अस्पतालों में बर्न, ईएनटी और इमरजेंसी सेवाओं को विशेष रूप से तैयार रखा जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में घायलों को तत्काल उपचार मिल सके।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बुधवार को बताया कि दीपावली पर आतिशबाजी या अन्य दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के इलाज में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आपातकालीन केंद्रों में जरूरी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की



जाए। इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और बर्न ट्रीटमेंट किट पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आतिशबाजी और अन्य दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में 20 से अधिक बेड आरक्षित रखे जाएंगे। दीपावली के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं, आग से झुलसने और आंखों में चोट लगने की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है।

इसे देखते हुए इमरजेंसी विभाग के साथ-साथ नेत्र रोग, हड्डी रोग और सर्जरी विभागों में भी अतिरिक्त बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेत्र रोग, हड्डी रोग और सर्जरी विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। इन विशेषज्ञों को ऑन-कॉल ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत बुलाकर मरीजों का उपचार किया जा सके। दीपावली के दिन किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अस्पतालों में आग से झुलसने वाले मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, बेड, आईवी स्टैंड, आईवी सॉल्यूशन और एंटीबायोटिक्स उपलब्ध रखने को कहा गया है। इसके अलावा आपातकालीन केंद्रों में ऑक्सीजन और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का जोर इस बात पर है कि दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उपचार के लिए इंतजार न करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली के दौरान चिकित्सा कर्मियों और विशेषज्ञों को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देने के निर्देश भी दिए हैं। नेत्र रोग और ईएनटी विशेषज्ञों की टीमें अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगी। गंभीर मरीजों के त्वरित उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में भी विशेष रूप से बेड आरक्षित किए जाएंगे।

नारनौल के बिगोपुर गांव में खारे पानी से परेशान ग्रामीण टीडीएस 3000 पार

भारतेन्दु संवादाता, नारनौल। हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के गांव बिगोपुर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गांव में वाटर सप्लाई के माध्यम से पहुंच रहे पानी के खारे होने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का दावा है कि पेयजल में टीडीएस (टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स) की मात्रा 3000 से अधिक पहुंच गई है। इससे गांव की करीब तीन हजार की आबादी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, ट्यूबवेल से सप्लाई होने वाले पानी का स्वाद खारा है और इसे पीने में परेशानी हो रही है। लोगों ने पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग से समस्या का समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना जरूरी है, ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। मामले को गंभीरता से लेते हुए नारनौल जनस्वास्थ्य विभाग ने पानी की गुणवत्ता की जांच करवाने की बात कही है। जांच के लिए पानी के नमूने लिए जाएंगे, जिससे टीडीएस की वास्तविक मात्रा और पेयजल की स्थिति का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जांच के बाद ही पानी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच जल्द पूरी कराकर खराब पानी की सप्लाई बंद की जाए और गांव में स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

◆ पेयजल में टीडीएस 3000 पार होने का दावा

रेवाड़ी में प्रदूषण का कहर, स्मॉग से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी



रेवाड़ी में स्मॉग का कहर, एक्यूआई 310

भारतेन्दु संवादाता, रेवाड़ी। दीवाली से पहले ही रेवाड़ी में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। बुधवार सुबह जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 310 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। इससे लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय धुंध और प्रदूषण के मिश्रण से दृश्यता भी प्रभावित हुई। सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

दीवाली के नजदीक आने के साथ ही प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आतिशबाजी के साथ-साथ सड़कों पर उड़ती धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ने का कारण बन सकता है।

ऐसे में लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शहरवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

रोहतक में तीन पीढ़ियों से कायम है बताशे बनाने का पारंपरिक हुनर

दादा दिलबाग ने शुरू किया था कारोबार, पिता ने बढ़ाई परंपरा

भारतेन्दु संवादाता, रोहतक। बदलते समय के साथ मिठाइयों के स्वाद और उन्हें बनाने के तरीकों में काफी बदलाव आया है, लेकिन रोहतक में आज भी एक परिवार पारंपरिक तरीके से बताशे बनाने की कला को संजोए हुए है। यहां एक-दो नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों से यह काम किया जा रहा है।

दादा से शुरू हुआ यह कारोबार अब पोते तक पहुंच चुका है। परिवार की मेहनत और हुनर से तैयार होने वाले बताशों की आपूर्ति रोहतक के साथ-साथ प्रदेश के कई बाजारों में की जाती है। शहर के शोरा कोठी निवासी दिवेश ने बताया कि उनके दादा



चीनी की चाशनी से तैयार होते हैं गोल-मटोल बताशे।

दिलबाग ने सीमित संसाधनों के बीच मेहनत और लगन से इस कारोबार की शुरुआत की थी। उस समय सुविधाएं कम थीं, लेकिन उन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर बताशे बनाने का काम खड़ा किया। इसके बाद उनके पिता नरेंद्र भी इस कारोबार से जुड़ गए और उन्होंने पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया। अब तीसरी पीढ़ी भी इसी काम में जुटी हुई है। बताशों की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले त्योहारों के दौरान बढ़ जाती है। खासकर दीपावली और अन्य धार्मिक अवसरों पर इनकी खपत अधिक रहती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए परिवार की ओर से उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। जानकारी के अनुसार, त्योहारी सीजन में रोजाना करीब आठ से नौ क्विंटल बताशे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए सालारा मोहल्ले में दो गोदामों में काम किया जा रहा है।

बताशे बनाने की प्रक्रिया में पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी और पानी से तैयार चाशनी इस मिठाई का मुख्य आधार होती है। चाशनी की सही स्थिति और उसे संभालने का हुनर ही बताशों को उनका खास आकार देने में महत्वपूर्ण होता है। इस काम में अनुभव की भी अहम भूमिका रहती है।

द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में डेढ़ घंटे तक जाम में फंसे रहे हजारों वाहन

भारतेन्दु संवादाता, गुरुग्राम। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले लोगों को बुधवार सुबह भीषण जाम का सामना करना पड़ा। द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल और उसके आसपास के रास्तों पर सुबह करीब साढ़े आठ बजे से वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण लंबा जाम लग गया। इसमें हजारों वाहन चालक फंस गए। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और अपने गंतव्य की ओर निकले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि जिस रास्ते को तय करने में आमतौर पर महज 15 मिनट लगते हैं, वहां वाहन चालकों को डेढ़ घंटे से भी अधिक समय लगा। द्वारका सेक्टर-21 से गुरुग्राम के एंबियंस मॉल तक वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। टनल के भीतर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। अचानक लगे जाम के कारण सुबह के समय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। हैरानी की बात यह रही कि गुरुग्राम की तरफ हाईवे पर यातायात सामान्य और सड़कें खाली नजर आईं, जबकि दिल्ली सीमा में प्रवेश करते ही वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सीमा और टनल के भीतर वाहनों का भारी दबाव बना रहा। इस कारण दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

हरियाणा में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का तीन महीने से भत्ता अटका, भुगतान नहीं

ई-सैलरी पोर्टल में तकनीकी खराबी से भुगतान तीन महीने से लंबित

भारतेन्दु संवादाता, सोनीपत। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टर पिछले तीन महीने से स्पेशलिस्ट अलाउंस नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। डॉक्टरों को हर महीने वेतन के साथ 10,200 रुपये का विशेष भत्ता दिया जाता है, लेकिन ई-सैलरी पोर्टल में तकनीकी दिक्कत के चलते इसका भुगतान अटक गया है। इससे प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



डॉक्टरों के अनुसार, ई-सैलरी पोर्टल में आई तकनीकी समस्या के कारण भत्ते की भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग के महानिदेशक की ओर से 3 अगस्त 2026 को पोर्टल अनफ्रीज करने संबंधी पत्र भी जारी किया गया था। इसके बावजूद अब तक विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाते में लंबित भत्ते की राशि नहीं पहुंची है।

सोनीपत के सरकारी अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है। उन्होंने ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायत भेजकर भुगतान शुरू करवाने और तकनीकी समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि जब पोर्टल अनफ्रीज करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं तो इसके बावजूद भुगतान में देरी समझ से परे है।

डॉक्टरों ने जल्द भुगतान की उठाई मांग

डॉक्टरों ने संबंधित विभाग से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि उन्हें पिछले तीन महीनों से लंबित भत्ते की राशि मिल सके। उनका कहना है कि स्पेशलिस्ट अलाउंस विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनकी अतिरिक्त योग्यता और सेवाओं के लिए दिया जाता है। ऐसे में तकनीकी कारणों से इसका भुगतान लंबे समय तक रोके रखना उचित नहीं है। डॉक्टरों ने मांग की है कि ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग पोर्टल से जुड़ी सभी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करे। साथ ही लंबित भुगतान जारी करने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की जाए। इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को राहत मिल सकेगी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी।

देश में 16 नई स्वदेशी पशु नस्लों को राष्ट्रीय पहचान मिलने से कुल संख्या 262 हुई

एनबीएजीआर ने स्वदेशी पशु नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा दिया

भारतेन्दु संवादाता, करनाल। देश के अलग-अलग राज्यों में पीढ़ियों से पाली जा रही स्वदेशी पशु नस्लों को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की नौ पशु प्रजातियों की 16 नई स्वदेशी नस्लों को पंजीकृत किया है। इसके साथ ही देश में पंजीकृत पशुधन एवं कुक्कुट नस्लों की कुल संख्या बढ़कर 262 हो गई है।

इस उपलब्धि को देश की स्वदेशी पशु संपदा और उसकी आनुवंशिक विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों



◆ पशुधन की कुल पंजीकृत नस्लों का आंकड़ा 262 पहुंचा

में अलग-अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पशुओं की विशिष्ट नस्लें विकसित हुई हैं। कहीं गर्म जलवायु के अनुकूल गायें पाली जाती हैं तो कहीं पहाड़ी इलाकों में याक जैसी प्रजातियां पनपती हैं। इसी तरह भेड़ और बकरियों की भी कई स्थानीय नस्लें हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं।

स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को मिलेगी मजबूती

इनके अलावा कुत्ते, घोड़े और गधों की भी कई स्वदेशी नस्लें हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान रखती हैं। इन नस्लों का पंजीकरण होने से उनकी विशिष्ट आनुवंशिक विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। साथ ही इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाबद्ध प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय नस्लें अपने क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं।

कार्रवाई आरडब्ल्यूए की शिकायत पर टाउन प्लानिंग विभाग ने डीएलएफ के खिलाफ कार्रवाई की

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 में अवैध डीजी सेट हटाने का आदेश

भारतेन्दु संवादाता, गुरुग्राम। डीएलएफ सिटी फेज-1 में पार्कों, ग्रीन बेल्ट और खुले स्थानों पर लगाए गए अनधिकृत डीजल जनरेटर (डीजी) सेट को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट कार्यालय ने डीएलएफ लिमिटेड और डीएलएफ सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सात दिन का समय दिया है।

विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी अवैध जनरेटर हटाए जाएं और जिन स्थानों पर इन्हें लगाया गया है, उन्हें पहले की स्थिति में बहाल किया जाए। इस कार्रवाई के बाद डीएलएफ फेज-1 में जनरेटरों को लेकर विवाद गहरा गया है। एक



अवैध डीजी सेट हटाने के विभागीय निर्देश।

तरफ सार्वजनिक उपयोग के पार्कों, ग्रीन बेल्ट और खुले स्थानों पर अनधिकृत जनरेटर लगाए जाने का मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ इन जनरेटरों से बिजली बैकअप की सुविधा प्राप्त कर रहे सैकड़ों परिवारों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। जनरेटर हटने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई डीएलएफ फेज-1 के ए ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर शिकायत के बाद की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य एंडले हैं। इस मामले को मूल आवेदन संख्या 451/2026 के तहत डीएलएफ फेज-1 ए ब्लॉक आरडब्ल्यूए बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के नाम से दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद संबंधित विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनधिकृत डीजी सेट हटाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने डीएलएफ लिमिटेड और आरडब्ल्यूए दोनों को जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा है।

सात दिन में जनरेटर हटाने होंगे

विभागीय निर्देशों के अनुसार, सात दिन की समयसीमा में सभी अनधिकृत जनरेटर हटाने की जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की होगी। इसके साथ ही जनरेटर हटाने के बाद पार्कों और ग्रीन बेल्ट में हुए बदलावों को भी ठीक करना होगा, ताकि सार्वजनिक स्थानों का उपयोग पहले की तरह किया जा सके। इस मामले में विभाग की कार्रवाई को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, स्थानीय निवासियों के सामने बिजली बैकअप की वैकल्पिक व्यवस्था का सवाल भी खड़ा हो गया है। यदि जनरेटर हटाए जाते हैं तो बिजली कटौती के दौरान सैकड़ों परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डीएलएफ प्रबंधन और आरडब्ल्यूए को विभागीय आदेशों का पालन करने के साथ-साथ निवासियों की बिजली संबंधी जरूरतों के लिए भी उचित व्यवस्था करनी होगी।

स्कूल पहुंची थी पढ़ने, लेकिन घर नहीं लौटी 9 वर्षीय प्रगति, अचानक मौत से परिवार में मातम

एजेंसी, नई दिल्ली



स्कूल में अचानक गिरी तीसरी कक्षा की छात्रा, मौत।

पूर्वी दिल्ली के माया विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा प्रगति की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल परिसर में चलते-चलते अचानक जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और अन्य छात्रों में शोक का माहौल है।

चलते-चलते अचानक जमीन पर गिर गई छात्रा

जानकारी के अनुसार, माया विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल में 9 वर्षीय प्रगति तीसरी कक्षा की छात्रा थी। स्कूल में सामान्य गतिविधियों के दौरान वह अचानक धीरे-धीरे झुकने लगी और देखते ही देखते जमीन पर गिर गई। इस पूरी घटना का वीडियो स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची को अचानक नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। बच्ची के अचानक गिरने से स्कूल में मौजूद लोग घबरा गए।

इसके बाद उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। छात्रा को निरमन विहार स्थित मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। **सुबह 9:52 बजे पुलिस को मिली सूचना**

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 9:52 बजे पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को एक कॉल प्राप्त हुई थी।

कॉल करने वाले ने जानकारी दी कि माया विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा को निरमन विहार के मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर अस्पताल लाया गया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पुलिस स्कूल परिसर में हुई घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। साथ ही घटना के समय मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। **सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना** इस मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने सभी को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि बच्ची चलते-चलते अचानक धीरे-धीरे झुकने लगती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। हालांकि, बच्ची की अचानक मौत के पीछे क्या कारण रहा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। **मौत की वजह जानने के लिए जांच जारी**

महज 9 साल की बच्ची की स्कूल में अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, स्कूल प्रबंधन भी इस घटना से सकते में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बच्ची की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

सनी देओल की फिल्म पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका सुनने से किया इनकार

एजेंसी, नई दिल्ली



फिल्म के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की।

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूयाः अंत से आरंभ तक' रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। फिल्म के टीजर में दिखाए गए कथित आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, बुधवार को अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि मेडिकल समुदाय की ओर से इसी मुद्दे पर पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ विचार कर रही है।

ऐसे में समान मुद्दे पर अलग से सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। **फिल्म के टीजर के दृश्यों पर जताई गई थी आपत्ति**

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि फिल्म के टीजर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों को भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाया गया है।

आरोप लगाया गया कि इसमें डॉक्टरों को मरीजों का शोषण करते, बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाते और अनावश्यक जांच करवाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा को वीरतापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

ब्राह्मण सभा का बड़ा फैसला, पंडित केएस शर्मा को बनाया उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष

एजेंसी ,नई दिल्ली नोएडा। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा (पंजी) ने सेक्टर-99 एचआईजी फ्लैट सोसायटी निवासी पंडित केएस शर्मा को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंगलवार को नोएडा में आयोजित संगठन की बैठक के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने उन्हें पटका पहनाकर नियुक्ति पत्र सौंपा। बैठक सेक्टर-52 स्थित राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक के आवास पर आयोजित हुई। इसमें राष्ट्रीय प्रभारी केसी गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री एके शर्मा और प्रदेश महामंत्री पंडित कमलकांत शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में समाज की उन्नति, संगठन की मजबूती और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद पंडित केएस शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। संगठन ने उन्हें दो महीने के भीतर अपनी प्रदेश कार्यकारिणी गठित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है।



दिल्ली पुलिस के निलंबित एसीपी पर गंभीर आरोप, वकीलों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में गुहार

एजेंसी, नई दिल्ली नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वकीलों को कथित तौर पर एके47 से धमकी देने और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इस पर अदालत ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। वकीलों की सुरक्षा की मांग अधिवक्ता करण बीर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ सहित कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ताओं को धमकाया गया और सार्वजनिक रूप से उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। याचिका में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है। अब इस मामले में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।



आगरा समेत कई नामों पर आपत्ति, भाजपा ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की सूची वापस

एजेंसी, नई दिल्ली आगरा। भाजपा ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की नई कार्यसमिति की सूची विवादों में घिर गई है। 30 अक्टूबर को जारी की गई 39 पदाधिकारियों की सूची में कुछ नामों पर आपत्ति उठने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने इसे रोक दिया। सूची जारी होने के कुछ घंटे बाद ही पदाधिकारियों ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। फिलहाल नई सूची दोबारा जारी नहीं हुई है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी ने 30 अक्टूबर को कार्यसमिति की घोषणा की थी। इसमें आगरा की उपमा गुप्ता को उपाध्यक्ष, रंजना पंवार को महामंत्री और शशि को कार्यालय मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा ज्योति जादौन को आईटी संयोजक, प्रियंका दुबे को सोशल मीडिया संयोजक और प्रतिमा भार्गव को कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी। सूची में शामिल कुछ नामों को लेकर आपत्तियां सामने आने के बाद संगठन में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने हस्तक्षेप करते हुए सूची पर रोक लगा दी। अब नई कार्यसमिति की संशोधित सूची जारी होने का इंतजार है। भाजपा ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की कार्यसमिति सूची विवादों में घिर गई। 39 पदाधिकारियों के नामों पर आपत्ति के बाद प्रदेश नेतृत्व ने सूची रोक दी।

बाल्मीकि मोहल्ले में पसरा मातम: सोनू, अनिल और रवि की मौत, अभिषेक अस्पताल में भर्ती

एजेंसी, नई दिल्ली



एआई जेनरेटेड इमेज

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गौर चौक पर लंबे समय से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए गौर चौक अंडरपास को 5 नवंबर से तीन दिन के ट्रायल के तौर पर खोला जा रहा है। इस दौरान अंडरपास से वाहनों की आवाजाही शुरू कर यातायात व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। इससे नोएडा और सूरजपुर की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को भविष्य में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। **तीन दिन तक चलेगा ट्रायल** अंडरपास को ट्रायल के दौरान आम वाहनों के आवागमन के लिए खोला जाएगा।

इस दौरान संबंधित अधिकारी यातायात व्यवस्था पर नजर रखेंगे और वाहनों की आवाजाही में आने वाली परेशानियों का आकलन करेंगे। ट्रायल के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर करने के बाद ही इसे स्थायी रूप से जनता के लिए खोला जाएगा। **सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की होगी जांच**

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, तीन दिवसीय ट्रायल के दौरान अंडरपास की सुरक्षा व्यवस्था, साइनेज, लाइटिंग, जल निकासी और यातायात प्रबंधन की बारीकी से जांच की जाएगी।

इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो रही है या नहीं। **स्थायी रूप से खोलने की तारीख तय नहीं** गौर चौक पर लंबे समय से लगने वाले जाम के कारण ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हजारों लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंडरपास शुरू होने से इस समस्या में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इसे स्थायी रूप से खोलने की तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

आगरा में डंपर का कहर, कोचिंग जा रही नौवीं की छात्रा को कुचला, दर्दनाक मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में नौवीं कक्षा की छात्रा की जान चली गई। सदर क्षेत्र के मधु नगर में आरएमओ चौराहे के पास गिट्टी से लदे डंपर ने स्कूटी सवार छात्रा रिया को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि छात्रा स्कूटी समेत डंपर के अगले पहिये के नीचे फंस गई। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, सदर क्षेत्र के सेवला निवासी उमेश की बेटी रिया कक्षा नौ में पढ़ती थी। बुधवार सुबह करीब आठ बजे वह स्कूटी से कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान आरएमओ चौराहे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। **आधे घंटे की मशक्कत के बाद निकाली गई छात्रा** हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। छात्रा स्कूटी समेत डंपर के अगले पहिये के नीचे फंस गई थी।

सीबीएसई 12वीं के छात्रों को मिलेगी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की छूट ? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एजेंसी, नई दिल्ली



कैलकुलेटर इस्तेमाल की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। एआई इमेज

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को बेसिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई सहित अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने सभी पक्षों को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। **बेसिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की मांग** यह जनहित याचिका विभिन्न अभिभावकों की ओर से दायर की गई है।

इसमें मांग की गई है कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को बेसिक नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गणित और अकाउंटेंसी जैसे विषयों में छात्रों को लंबी गणनाएं हाथ से करनी पड़ती हैं। इसमें परीक्षा का काफी समय खर्च हो जाता है। **गणना में समय खर्च होने से प्रभावित होती है पढ़ाई**

याचिका में तर्क दिया गया है कि लंबी गणनाओं में अधिक समय लगाने के कारण विद्यार्थियों को प्रश्नों को समझने और अपनी विषय संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ऐसे में बेसिक कैलकुलेटर की अनुमति मिलने से छात्र गणना में लगने वाला समय बचाकर विषय की समझ और प्रश्नों के समाधान पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, सीबीएसई और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सभी की नजर 27 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी। फिलहाल अदालत ने छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

नोएडा एयरपोर्ट पर जुलाई के बाद लगातार गिरा यात्री ग्राफ, सितंबर में 55,890 लोगों ने किया सफर

एजेंसी, नई दिल्ली



नोएडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या घटी। एआई इमेज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में शुरुआती बढ़ोतरी के बाद लगातार दो महीने गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई से सितंबर के बीच यात्रियों की संख्या में करीब 27 प्रतिशत की कमी आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के मासिक यातायात आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जहां 76 हजार से अधिक यात्रियों ने सफर किया था, वहीं सितंबर में यह संख्या घटकर करीब 56 हजार रह गई। हालांकि, अक्टूबर में नई उड़ानें शुरू होने से यात्रियों की संख्या में दोबारा बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। **दो महीने में करीब 27 प्रतिशत गिरावट**

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 76,593 यात्रियों ने हवाई सफर किया था। इसके बाद अगस्त में यात्रियों की संख्या घटकर 58,520 रह गई। सितंबर में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा और कुल 55,890 यात्रियों ने एयरपोर्ट से यात्रा की। आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई की तुलना में सितंबर में 20,703 यात्री कम हुए हैं। इस तरह महज दो महीने के भीतर यात्रियों की संख्या में लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। लगातार घटते यात्री आंकड़े एयरपोर्ट के शुरुआती परिचालन के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। **जून से सितंबर तक 2.11 लाख यात्रियों ने किया सफर** नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून 2026 से व्यावसायिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ था।

शुरुआत के दिनों में यात्रियों की संख्या सीमित रही। जून के शेष दिनों में कुल 20,522 यात्रियों ने हवाई सफर किया था। इसके बाद जुलाई में यात्रियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली और यह आंकड़ा 76,593 तक पहुंच गया। हालांकि, अगस्त और सितंबर में यात्रियों की संख्या में गिरावट आने से शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रह सकी।

अमेठी में सामूहिक विवाह की तैयारियां पूरी, 200 से अधिक जोड़ों की होगी शादी

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के तिलोई में आगामी 5 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 200 से अधिक जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन राजा विश्वनाथ शरण सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए संबंधित विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों और उनके परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कर्मचारियों की अलग-अलग जिम्मेदारियां तय कर ड्यूटी लगाई गई है। **दुल्हनों को मिलेगा सरकारी सहायता का लाभ** मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

दिवाली पर योगी सरकार की सौगात, उज्ज्वला लाभार्थियों को मिले 639 .50 रुपये के चेक

एजेंसी, नई दिल्ली



प्रतीकात्मक फोटो

मेरठ। दीपावली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलिंडर और सब्सिडी की राशि का चेक प्रदान किया। मेरठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को दीपावली का खास तोहफा दिया गया। इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत मिली। कार्यक्रम का आयोजन मेरठ के विकास भवन सभागार में किया गया। यहां करीब 250 लाभार्थियों ने लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा।

इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन और योजना से जुड़ी घोषणाओं को भी लाभार्थियों ने सुना। 20 लाभार्थियों को सौंपे गए गैस सिलिंडर और चेक कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 20 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से निशुल्क गैस सिलिंडर और सब्सिडी की राशि का चेक वितरित किया। प्रत्येक लाभार्थी को 639.50 रुपये का प्रतीकात्मक चेक सौंपा गया। इस मौके पर लाभार्थियों को बताया गया कि सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से होने वाली परेशानियों से बचाना और रसोई में स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

गुरुग्राम में प्रदूषण का कहर, 16 दिन निर्माण कार्यों पर रोक; दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम



गुरुग्राम में प्रदूषण से निर्माण कार्यों पर रोक।

एजेंसी, नई दिल्ली गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में 5 से 20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त उत्तम सिंह ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत मंगलवार को यह आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर लागू होगा। हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है। मंगलवार को गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 दर्ज किया गया, जो इस सीजन में पहली बार बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई प्रशासन ने एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को रोजाना निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में प्रदूषण का कहर, 16 दिन निर्माण कार्यों पर रोक और सरकारी-निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। गुरुग्राम में प्रदूषण से बिगड़े हालात, वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 पहुंचा। प्रशासन ने 16 दिन निर्माण कार्यों पर रोक लगाई, दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए।

खत्म हुआ खान सर और अंजना ओम कश्यप का विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ समझौता

हाई-प्रोफाइल मानहानि केस में बड़ा मोड़, खान सर और अंजना ओम कश्यप के बीच सुलह

एजेंसी, नई दिल्ली



अंजना ओम कश्यप खान सर विवाद।

पत्रकार अंजना ओम कश्यप और चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच लंबे समय से चल रहा मानहानि का विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों ने दिल्ली हाईकोर्ट में आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया है। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से समझौते की जानकारी दिए जाने के बाद मानहानि याचिका का निपटारा कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही दोनों के बीच चल रहे हाई-प्रोफाइल कानूनी विवाद पर विराम लग गया है।

मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान पत्रकार अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा भंडारी ने अदालत को बताया कि खान सर समेत मामले के सभी छह प्रतिवादियों के साथ विवाद सुलझ गया है। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब इस मामले को आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, दोनों पक्षों के वकीलों ने भी अदालत के सामने आपसी समझौते की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकाल लिया गया है। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति को रिकॉर्ड पर लेते हुए समझौते के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया। दरअसल, अंजना ओम कश्यप ने सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट किए जाने को लेकर खान सर सहित अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद शुरू हुआ था। मामले में खान सर के अलावा पांच अन्य प्रतिवादियों को भी शामिल किया गया था।

अंजना ओम कश्यप की ओर से अदालत में दायर याचिका के बाद यह विवाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा। दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने पक्ष रखे गए और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन रहा। हालांकि, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकल आया। आपसी चर्चा के बाद सभी छह प्रतिवादियों के साथ समझौता होने की जानकारी अदालत को दी गई। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे चलाने की आवश्यकता नहीं समझी और याचिका का निपटारा कर दिया।

इस तरह पत्रकार अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच चल रहा मानहानि का मामला अब आपसी सहमति से समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद इस हाई-प्रोफाइल विवाद पर कानूनी रूप से विराम लग गया है। पत्रकार अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच चल रहा मानहानि विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। अदालत ने समझौते को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। इस मामले में खान सर समेत छह प्रतिवादी शामिल थे। अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच मानहानि विवाद खत्म हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसी समझौते के बाद याचिका निपटा दी।

दिल्ली में होली के दिन चाकू से काटा था गला, हत्यारे को उम्रकैद

एजेंसी, नई दिल्ली



कड़कड़डूमा कोर्ट ने रंजीत को उम्रकैद सुनाई।

दिल्ली के सीमापुरी इलाके में वर्ष 2025 में होलिका दहन के दिन पुरानी रंजिश के चलते ठाकुर दास की बेरहमी से गला काटकर हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने वारदात के महज दो महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। करीब डेढ़ साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड की जांच में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट बेहद अहम साबित हुई। जांच के दौरान घटनास्थल से आरोपी रंजीत के फिंगरप्रिंट मिले थे। इन फिंगरप्रिंट ने आरोपी के खिलाफ मामले को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक ठाकुर दास की पत्नी पूनम और घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज किए थे।

पुलिस ने गवाहों के बयानों, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट को जांच का आधार बनाया। इन सबूतों को अदालत में पेश किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ अपना मामला साबित करने में मदद मिली। पुलिस के अनुसार, 13 मार्च 2025 को शाम करीब पांच बजे ठाकुर दास अपनी पत्नी पूनम के साथ होली की खरीदारी करके घर लौट रहे थे।

जब वे सीमापुरी की कब्रिस्तान रोड पर जैन मंदिर के पास पहुंचे, तभी आरोपी रंजीत ने उनका रास्ता रोक लिया। इस दौरान आरोपी ने ठाकुर दास के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बताया गया कि दोनों के बीच पहले से रंजिश चल रही थी। इसी विवाद के चलते आरोपी ने चाकू से ठाकुर दास का गला काट दिया। होली के त्योहार की तैयारियों के बीच हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी।

न्यूज ब्रीफ

सौरभ ने विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी देवरा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में विद्यालय के पूर्व छात्र सौरभ शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सौरभ शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ अपने स्कूली जीवन की यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी विद्यालय से पहली कक्षा से शिक्षा प्राप्त की है। आज उसी विद्यालय में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचना उनके लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और हौसला बनाए रखना जरूरी है। समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य, पंचायत उपप्रधान वीरेंद्र (इच्छा), वार्ड पंच, एसएमसी सदस्य, शिक्षकगण और अभिभावक उपस्थित रहे।

मेहंदी प्रतियोगिता में संजना रही प्रथम



भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर। राजकीय महाविद्यालय रिवालसर की सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज की 24 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक समिति की संयोजक डॉ. अंजलि परमार ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्राओं ने आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में डॉ. कुलदीप कुमार और प्रो. रमणीक शर्मा शामिल रहे। प्रतियोगिता में बीए अंतिम वर्ष की संजना ने प्रथम, बबिता ठाकुर ने द्वितीय तथा प्रथम सेमेस्टर की दीपिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ब्रज नंदन ने विजेता छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नवंबर में कुल्लू के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होंगे राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा नवंबर माह में जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सांख्यिकीय सर्वेक्षण करवाए जाएंगे। इन सर्वेक्षणों में श्रम बल, असंगठित क्षेत्र के उद्यम, घरेलू आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, प्रवासन, ऋण एवं निवेश तथा कृषि परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। कराड़, शमशी, मनाली, कुल्लू, मणिकर्ण और रशाला सहित विभिन्न क्षेत्रों को इसके लिए चयनित किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान प्रशिक्षित अधिकारी डिजिटल उपकरणों के माध्यम से चयनित परिवारों और प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र करेंगे। एनएसओ ने स्पष्ट किया है कि सभी आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होगा। कार्यालय ने चयनित परिवारों एवं संस्थानों से सही जानकारी उपलब्ध करवाकर सर्वेक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

बंजार में स्वच्छता सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) बंजार के कार्यालय ने एसडीएम कार्यालय बंजार, तहसील कार्यालय बंजार और तहसील कार्यालय सैंज के भवनों एवं परिसरों में स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पात्र ठेकेदारों और फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। इच्छुक ठेकेदार व फर्म अपनी निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर 12 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे तक एसडीएम कार्यालय बंजार में जमा करवा सकते हैं। निविदाएं इसी दिन दोपहर 3 बजे इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। निविदा दस्तावेज जिला प्रशासन कुल्लू की वेबसाइट अथवा एसडीएम कार्यालय बंजार से 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त या अधूरी निविदाएं निरस्त की जा सकती हैं। निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार एसडीएम बंजार के पास सुरक्षित रहेगा।

विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व बताया

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। जोगिंद्रनगर के शांति निकेतन स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में माइंड ऑपरेशन एकेडमी के संस्थापक राम प्रकाश ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल के संस्थापक विकास, जनरल सेक्रेटरी विवेक और प्रधानाचार्य कंचन ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर राम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के साथ अनुशासन, संस्कार और आत्मविश्वास का विशेष महत्व है। आज के बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा देना शिक्षकों व अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विद्यार्थियों की मेहनत और प्रतिभा को सम्मान देने का बेहतरीन मंच हैं। पुरस्कार मिलने से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समारोह के दौरान शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने स्कूल प्रबंधन को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

संधोल में रोएंदार इल्लियों का प्रकोप, पेड़-पौधों को नुकसान की आशंका

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। सरकाघाट क्षेत्र के संधोल में इन दिनों रोएंदार इल्लीनुमा कीटों की बढ़ती संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहली बार दिखाई दे रहे इन कीटों का लसराणा से दतवाड़ मार्ग पर काफी प्रकोप है। ये कीट विशेष रूप से गों के पेड़ों की पत्तियां खा रहे हैं, जिससे वनस्पति और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्थानीय स्तर पर सामने आई तस्वीरों में इन कीटों के शरीर पर लंबे सफेद बाल और लाल-गुलाबी रंग के उभरे हुए गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनकी लंबाई करीब 2 से 4 सेंटीमीटर बताई जा रही है। कुछ रोएंदार इल्लियों के बाल त्वचा में खुजली और जलन भी पैदा कर सकते हैं। स्थानीय निवासी नीलम, जीत सिंह, भूमि सिंह और कमलजीत ने बताया कि मार्ग पर जगह-जगह इनका प्रकोप है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से कीटों की पहचान करवाकर जल्द रोकथाम करने की मांग की है। उधर, स्थानीय वन रक्षक मनीष ने कहा कि उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। वह इस संबंध में जानकारी जुटाएंगे।

शाहपुर के भाजपा नेता राकेश चौहान का आकस्मिक निधन, विधायक पठानिया ने जताया शोक

भारतेन्दु संवाददाता, शाहपुर। शाहपुर के भाजपा नेता राकेश चौहान के आकस्मिक निधन पर शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। राकेश चौहान के शाहपुर अस्पताल में होने की सूचना मिलते ही विधायक अस्पताल पहुंचे। उनके निधन का समाचार मिलने के बाद उन्होंने अपने आज के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसके बाद केवल सिंह पठानिया नौण स्थित श्मशान घाट पहुंचे और दिवंगत राकेश चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। विधायक ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

बोह स्कूल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यटन में रोजगार के अवसरों की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में व्यावसायिक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसमें न्यूएस संस्थान के दिनेश शर्मा और प्रतीक धीमान ने विद्यार्थियों को जानकारी दी। दिनेश शर्मा ने कहा कि आज के दौर में केवल डिग्री हासिल करना नौकरी की गारंटी नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान, संवाद कौशल, रचनात्मकता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मशीनों के बढ़ते उपयोग के बावजूद मानवीय संवेदनाएं और सही निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण रहेंगी। वहीं, प्रतीक धीमान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े रोजगार अवसरों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को पर्यटन, डिजिटल प्रचार और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं से भी अवगत करवाया गया। साथ ही दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी तथा समय प्रबंधन पर जोर दिया गया।

नौणी विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर व वैश्विक पहचान दिलाना लक्ष्य : प्रो. बवेजा

बागवानी व वानिकी अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा, नौणी विवि ने शुरू कीं नई परियोजनाएं

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने संस्थागत विकास को नई गति देते हुए आत्मनिर्भरता, नवाचार, अनुसंधान व वैश्विक विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

विश्वविद्यालय में बुधवार को नई सुविधाओं का उद्घाटन करने के साथ ही विभिन्न अनुसंधान एवं शैक्षणिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। कुलपति प्रो. हरमिंदर सिंह बवेजा ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में इन योजनाओं का शुभारंभ किया। उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर के प्रसंस्करण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यहां मशरूम, फल, सब्जियों, मसालों और औषधीय



जड़ी-बूटियों के प्रसंस्करण, उत्पाद विकास तथा मूल्य संवर्धन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, विद्यार्थियों और नए उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त वाइन निर्माण से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एनोलॉजी प्रयोगशाला, हर्बल उत्पाद विकास एवं विक्रय केंद्र और हर्बेरियम के डिजिटलीकरण की सुविधा भी शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तपोषण से स्थापित कैनबिस अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से औषधीय उपयोग के लिए भांग का वैज्ञानिक अध्ययन और गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति केंद्र तथा सत्यनंद स्टोक्स पुस्तकालय में ब्रह्माकुमारी संस्थान के सहयोग से स्थापित थॉट लैब का भी शुभारंभ हुआ। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग में पौध ऊतक संवर्धन सुविधा, हिमालयी पारंपरिक बीज विरासत केंद्र, अपशिष्ट से संपदा उत्कृष्टता केंद्र और मधुमक्खी अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से अनुसंधान, पारंपरिक बीज संरक्षण, मधुमक्खी पालन और अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षण केंद्र, नेरी स्थित औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में प्रशिक्षण, नियोजन एवं वैश्विक संपर्क उत्कृष्टता केंद्र तथा कृषि संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। छात्रावासों में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए सुख-संसार रीडिंग एंड स्टडी लाउंज का भी उद्घाटन किया गया। कुलपति प्रो. बवेजा ने कहा कि ये पहल केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर, नवाचार आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे अनुसंधान, उद्यमिता, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर विकसित होंगे।

मटौर में नए पुल का निर्माण कार्य तेज, घंटों जाम से जूझ रहे लोग

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। कांगड़ा के साथ लगते मटौर में नए पुल का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से जारी है।

यह पुल यातायात की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मार्ग से पठानकोट, धर्मशाला, शिमला और दिल्ली सहित कई प्रमुख स्थानों के लिए वाहन गुजरते हैं। पुराना लोहे का पुल काफी जर्जर हो चुका था और बार-बार मरम्मत के सहारे चलाया जा रहा था। ऐसे में नए पुल का निर्माण जरूरी हो गया था। हालांकि, निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से कई बार घंटों तक जाम लग रहा है। इससे राहगीरों के साथ-साथ आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। जाम के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार मुल्का राम, पुष्पिंदर कुमार, राजू कुमार और निक्की कुमार ने बताया कि नया पुल बनना क्षेत्र के लिए जरूरी है और इससे भविष्य में यातायात सुविधा बेहतर होगी। लेकिन वर्तमान में निर्माण कार्य के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। पैदल चलने वाले लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दुकानदारों ने संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी से मांग की है कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि लोगों को घंटों जाम में न फंसना पड़े और स्थानीय कारोबारियों को भी राहत मिल सके।



◆ पठानकोट, धर्मशाला, शिमला और दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए अहम है पुल, निर्माण कार्य से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित

कुल्लू के कारोबारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगी

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जिला मुख्यालय कुल्लू में लॉरेंस गैंग के नाम पर एक कारोबारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

विदेशी मोबाइल नंबरों से आई धमकी भरी कॉल के बाद कारोबारी ने पुलिस थाना कुल्लू में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में कारोबारी तेजिंद्र सिंह ने बताया कि 2 नवंबर की रात करीब 8:02 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान विदेशी नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बताते हुए 10 लाख रुपये की मांग की और बैंक खाते की जानकारी भेजने की बात कही। कारोबारी ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। पहली कॉल के सात मिनट बाद रात 8:09 बजे दूसरे विदेशी नंबर से फोन आया।

कॉल करने वाले ने अगली सुबह तक रकम नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी। रात 8:11 बजे इसी नंबर से दोबारा कॉल आई, जिसके बाद कारोबारी ने उसे भी ब्लॉक कर दिया।

साइबर सेल खंगाल रही कॉल डिटेल

धमकी मिलने के बाद कारोबारी ने पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी और थाने में लिखित शिकायत सौंपी। एसपी अभिषेक एस ने बताया कि साइबर सेल की मदद से दोनों संदिग्ध मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वाले का वास्तव में लॉरेंस गैंग से कोई संबंध है या उसने केवल गैंग का नाम इस्तेमाल किया है। पुलिस कॉल करने वाले की पहचान और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

घट्टा टोल प्लाजा के विरोध में छह नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना देंगे ग्रामीण

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के चंगर की एक दर्जन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने घट्टा टोल प्लाजा को अंयत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर छह नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना व अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि टोल प्लाजा के पांच किलोमीटर दायरे में आने वाले वाहनों को टोल शुल्क से छूट दी जाए। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के संघर्ष के चलते 20 किलोमीटर दायरे के लिए सालाना 1500 रुपए का पास लागू किया गया है। इसके लिए सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और विधायक पवन काजल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जिसमें क्षेत्र की एक दर्जन पंचायतों के ग्रामीण भाग लेंगे। विधायक पवन काजल को भी धरने में आमंत्रित किया गया है।

खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान से युवाओं को नशे से दूर रखने का होगा प्रयास : यादविंदर गोमा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेलों से जोड़ने, खेल प्रतिभाओं को निखारने और चिट्टा सहित अन्य नशों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू होने वाले 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान-2026' की तैयारियों को लेकर बुधवार को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने की। यादविंदर गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश में पहली बार इस तरह का व्यापक खेल आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अभियान का शुभारंभ 20 नवंबर को एचपीसीए मैदान धर्मशाला में होगा। इस अवसर पर ड्रोन शो, लेजर शो और नामी कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जा रहा है तथा अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जा रही हैं। मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए छह खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं की शुरुआत गांव और पंचायत स्तर से होगी। इसके बाद उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर मुकाबले करवाए जाएंगे। प्रत्येक खेल श्रेणी में विजेता टीमों को पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री ने अधिकारियों के साथ एचपीसीए स्टेडियम में आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा, खेल विभाग के निदेशक शिवम प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस के बीच रणनीतिक साझेदारी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में बीमा सेवाओं की पहुंच मजबूत करने और ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी) और चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी हुई है।

इस समझौते के तहत अब बैंक के व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस के विभिन्न सामान्य बीमा उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक सरल, सुलभ और भरोसेमंद बीमा सुविधाएं पहुंचाना है। इसके तहत ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और संपत्ति बीमा सहित विभिन्न सामान्य बीमा उत्पादों का विकल्प मिलेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित किया



जाएगा। इस रणनीतिक साझेदारी को लेकर 4 नवंबर को मंडी में दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से चेयरमैन बॉबी तंवर, महाप्रबंधक कर्म वीर सिंह शेखावत और महाप्रबंधक राजीव कुमार रंजन उपस्थित रहे।

वहीं, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस की ओर से हेड-पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन अमित प्रकाश तिवारी, जोनल मैनेजर राजेश शर्मा, रीजनल मैनेजर अनिल कंबोज और एरिया मैनेजर अर्चना शर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह साझेदारी प्रदेश में वित्तीय समावेशन और बीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की व्यापक क्षेत्रीय पहुंच और ग्राहकों के बीच स्थापित विश्वास के साथ चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस की विशेषज्ञता एवं विविध बीमा उत्पादों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से आम लोगों के लिए बीमा सेवाएं अधिक सुलभ होंगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और प्रदेश में मजबूत बीमा तंत्र विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन : चंद्र प्रकाश

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर मंडी चंद्र प्रकाश ने बताया कि उपमंडल सदर के अंतर्गत अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक क्यूआर कोड स्कैन कर ई-हिमसेवा पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद अस्थायी पटाखा लाइसेंस से संबंधित विकल्प का चयन कर निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। एसडीएम ने बताया कि इच्छुक आवेदक संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने सभी आवेदकों से अपील की कि वे अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से आवेदन करें तथा आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

सराज की 3 पंचायतों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण, 75 लोगों ने सीखे बचाव के तरीके



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय, थुनाग स्थित गोहर द्वारा परियोजना 'हिमाचल प्रदेश में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए हिमालयी समुदायों का सशक्तिकरण' के तहत 2 से 4 नवंबर तक सराज विकास खंड की शरण, पखरैर और थुनाग पंचायतों में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें तीनों पंचायतों के कुल 75 लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में परियोजना की मुख्य अन्वेषक एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. कशिश वालिया ने आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा प्रतिरोधी समुदायों के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए स्थानीय समुदायों का जागरूक और प्रशिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने आपदा से पहले, दौरान और बाद में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों, सुरक्षित स्थानों की पहचान, आपातकालीन किट तैयार करने, प्राथमिक उपचार और राहत कार्यों में सहयोग के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा के अनुभव भी साझा किए तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। डॉ. वालिया ने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने गांवों में भी जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।

चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है कांग्रेस : सुमीत शर्मा

◆ 'युवा संवाद, विकसित भारत-2047' कार्यक्रम में युवाओं से किया संवाद

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। भाजपा प्रदेश सचिव व जिला शिमला प्रभारी सुमीत शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगती है, जबकि जीत मिलने पर यही पार्टी खामोश रहती है।



वह जिला कांगड़ा के दो निजी शिक्षण संस्थानों में आयोजित 'युवा संवाद, विकसित भारत-2047' कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार वर्ष 1951 से अब तक 10 बार एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई है, जिनमें आठ बार कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में हुई। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि पहले यही प्रक्रिया स्वीकार्य थी तो अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सुमीत शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सेना और मीडिया जैसी संस्थाओं पर राजनीतिक लाभ के लिए सवाल उठाती है। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस सरकारों में मिली राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तियों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

आज का युवा विकसित भारत, मजबूत लोकतंत्र और सशक्त राष्ट्र चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र चौधरी, प्रदीप शर्मा, कमल शर्मा, श्रेय अवस्थी, डॉ. सुकृत सागर, जसविंदर सिंह और साहिल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश इंटक का जनरल हाउस 14 नवंबर को शिमला में

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। प्रदेश इंटक का जनरल 14 नवंबर को शिमला में होगा। इंटक प्रदेश प्रवक्ता डीआर जोशी ने बताया कि केंद्रीय इंटक पर्यवेक्षक की देखरेख में चुनाव होंगे और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया



कि हिमाचल प्रदेश इंटक की 110वीं कार्यसमिति की बैठक 8 अक्तूबर को जगन पैलेस, घुमारवीं में आयोजित हुई थी, जिसमें शिमला में प्रदेश इंटक के पदाधिकारियों और कार्यसमिति सदस्यों के चुनाव के लिए जनरल हाउस आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि इसी निर्णय के तहत अब हिमाचल इंटक की जनरल हाउस और जनरल काउंसिल की बैठक 14 नवंबर 2026 को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों का पंजीकरण: सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक होगा। महान दूरदर्शी नेता और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जयंती पर स्मरण किया जाएगा। प्रदेश इंटक प्रवक्ता डीआर जोशी ने बताया कि सभी यूनियनों के लिए केंद्रीय इंटक का लंबित संबद्धता शुल्क 10 नवंबर, 2026 तक जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी यूनियनों से अनुरोध किया है कि चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम और संख्या 10 नवंबर तक अवश्य सूचित करें।

महिलाओं और बच्चों के कल्याणकारी कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी : उपायुक्त निवेदिता

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। उपायुक्त निवेदिता नेगी ने केलांग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना और कल्याण विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और विभाग के लंबित कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान डीसी ने विभागवार चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र वन स्ट

न्यूज ब्रीफ

कंदरौर पुल के समीप सतलुज नदी में मिला मंडी की 56 वर्षीय महिला का शव

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर के कंदरौर पुल के समीप सतलुज नदी में मंगलवार को एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में शव तैरता देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान तुला देवी (56), पत्नी स्वर्गीय छमारू राम, निवासी गांव व डाकघर शाला, तहसील चच्योट, जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस महिला की मौत के कारणों और बिलासपुर पहुंचने को लेकर विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

गंगे राम ठाकुर को मिली अहम जिम्मेदारी बने बिलासपुर सदर भाजयुमो के प्रभारी



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के सोझा गांव निवासी गंगे राम ठाकुर को भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त करने के साथ बिलासपुर सदर भाजयुमो का प्रभारी बनाया गया है। गंगे राम ठाकुर बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2010 में बंजार कॉलेज में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। वर्ष 2020 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा जिला कुल्लू का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने पर प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह युवा मोर्चा को मजबूत करने के लिए हर बूथ पर अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की मजबूती के लिए कार्य करेंगे।

सीएचसी उदयपुर में जल्द तैनात होंगे दो नए डॉक्टर, विधायक अनुराधा के प्रयास लाए रंग



भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। लाहौल-स्पीति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) उदयपुर में जल्द ही दो अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती होगी। विधायक अनुराधा राणा के प्रयासों से दोनों डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। विधायक अनुराधा राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोग और आशीर्वाद से सीएचसी उदयपुर के लिए दो अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित हुई है। दोनों डॉक्टर जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की तैनाती से उदयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राहत मिलेगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधायक ने कहा कि लाहौल-स्पीति में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भविष्य में भी निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

नशे के खिलाफ प्रशासन व समाज ने मिलाया हाथ, युवा बनेंगे जागरूकता की ताकत



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज में नशामुक्ति की अलख जगाने के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं। इसी कड़ी में एचवीटी फाउंडेशन के अभियान 'मिशन संभव-नशे के खिलाफ जंग' के तहत मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुश्रैणी के बाड़ी रोपा परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 210 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान एसडीएम बंजार पंकज शर्मा और एसएचओ बंजार ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी और इससे दूर रहने का आह्वान किया। 'कैच देम यंग' के संदेश के साथ अभियान के तहत युवाओं को जागरूकता दूत बनाकर गांव-गांव तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चमकी दधोगी की तेजस्वी, कांस्य पदक पर जमाया कब्जा



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत दधोगी की होनहार बेटी तेजस्वी शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डीएवी अंबुजा विद्या निकेतन दाड़लाघाट की छात्रा तेजस्वी ने दिल्ली-एनसीआर में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के अंडर-14 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। तेजस्वी की इस सफलता से विद्यालय सहित दधोगी पंचायत और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। छोटी उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उन्होंने अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा प्रस्तुत की है। तेजस्वी की उपलब्धि पर उनकी माता प्रियंका शर्मा और पिता प्रकाश चंद शर्मा सहित परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर की। वहीं, क्षेत्रवासियों ने भी छात्रा को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। लोगों ने उम्मीद जताई कि तेजस्वी भविष्य में भी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर प्रदेश का नाम रोशन करेगी।

राज्य स्तरीय मुक्केबाजी में बथालंग स्कूल के दो विद्यार्थियों ने जीते कांस्य पदक



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बथालंग के दो विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय के डीपीई अमित कुमार ने बताया कि छात्रा नितिका ने हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं, छात्र हितेश वर्मा ने मंडी में आयोजित प्रतियोगिता के 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों के विद्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानाचार्या उपासना सूद ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी सफलता का श्रेय डीपीई अमित कुमार और शारीरिक शिक्षक कामेश्वर के मार्गदर्शन एवं मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने दोनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

किसानों को दिया मल्चिंग शीट बिछाने का प्रशिक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (एचपीसीडीपी-जायका) के तहत बुधवार को छत्तर गांव में किसानों को मल्चिंग शीट बिछाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना से मसौली और छत्तर पंचायतों के कुल 361 परिवार लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. हेमराज वर्मा ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाकर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ लाभकारी नकदी फसलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि मल्चिंग शीट के उपयोग से मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार नियंत्रित होते हैं तथा सिंचाई और मजदूरी का खर्च कम होता है। लहसुन के अलावा प्याज, मटर और गोभी की खेती में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर मसौली-छत्तर कूहल का कार्य जल्द शुरू करने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में डॉ. आरके शर्मा, डॉ. अश्वनी कुमार, कृषि अधिकारी निशांत पाराशर सहित अन्य अधिकारी और किसान मौजूद रहे।

हमीरपुर जिले में चार महीनों के दौरान 26.26 करोड़ रुपए के खाद्यान्न वितरित

5,52,010 उपभोक्ताओं को 320 डिपुओं के माध्यम से दी जा रही है खाद्य सामग्री

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक बुधवार को उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में इस वर्ष जुलाई से अक्तूबर तक के चार महीनों के दौरान जिला में खाद्य सामग्री और रसोई गैस के वितरण तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर डीसी ने बताया कि इन चार महीनों के दौरान जिला के कुल 1,54,430 राशन कार्डों के 5,52,010 उपभोक्ताओं को 320 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कुल 26.26 करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सामग्री वितरित की गई। डीसी ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के



अधिकारियों से कहा कि जिला में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में नियमित रूप से निरीक्षण किए जाने चाहिए। गत चार महीनों के दौरान विभाग के अधिकारियों ने खाद्यान्नों के 55 सैंपल लिए थे, जिनमें से 4 सैंपल फेल पाए गए हैं। इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और गैस एजेंसियों के कुल 875 निरीक्षण किए गए हैं और तीन मामलों में अनियमितता पाए जाने पर लगभग 6463 की जुर्माना राशि भी वसूली गई है। इनमें पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के मामले भी शामिल हैं। डीसी ने बताया कि जिला के सभी 5,52,010 उपभोक्ताओं की आधार और मोबाइल नंबरों की सीडिंग हो चुकी है। लगभग 96 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शेष उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी अतिशीघ्र पूरी होनी चाहिए। जिले के 25 राशन डिपुओं में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई। समिति ने विभाग के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। उपायुक्त ने नादौन के बेला क्षेत्र में अत्याधुनिक खाद्यान्न एटीएम स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। जिला की सभी 10 गैस एजेंसियों में सिलेंडरों की उपलब्धता और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभिन्न योजनाओं एवं मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

महिलाओं को कानूनी अधिकारों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति किया जागरूक



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से बुधवार को जिला परिषद सभागार बिलासपुर में स्टॉकिंग, साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने की।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। डिजिटल युग में महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन अपराधों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी महिला का बार-बार पीछा करना या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना गंभीर अपराध है। महिलाओं को ऐसे मामलों में चुप रहने के बजाय शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की अपील की। साथ ही संदिग्ध लिंक, फर्जी वेबसाइट और अनजान कॉल से सावधान रहने तथा ओटीपी व बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में आयोग के विधि अधिकारी यशपाल शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत स्टॉकिंग के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। सीडीपीओ घुमारवीं रंजना ने महिला कल्याण योजनाओं, जबकि यूको बैंक के विजय दीवान ने डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा के बारे में बताया। एएसआई राजेंद्र सिंह ने साइबर अपराधों से बचाव और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी। इस अवसर पर आयोग की सदस्य रीना पुंडीर, नेहा वर्मा, सदस्य सचिव बुशरा अंसारी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न पंचायतों की महिला प्रधान उपस्थित रहीं।

कमीशन के लालच में विद्यार्थियों के बैंक खातों का दुरुपयोग, साइबर ठगी के पैसे का खुलासा

◆ दो दिल्ली निवासी युवकों को कुल्लू पुलिस ने जांच में किया शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। कमीशन का लालच देकर कॉलेज विद्यार्थियों व स्थानीय युवाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में किए जाने का मामला सामने आया है।

कुल्लू पुलिस ने इस मामले में दिल्ली निवासी दो युवकों को जांच में शामिल कर उनके मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं। पुलिस थाना सदर कुल्लू में 31 अक्तूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोग युवाओं को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम जमा करवाते थे। इसके बाद खाताधारकों से नकदी निकलवाकर अन्य लोगों को सौंपने के लिए कहा जाता था। जांच में कुछ संदिग्ध लेन-देन का संबंध दूसरे राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों से भी जुड़ा मिला है। पुलिस ने संबंधित बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगाया है। साथ ही ऑनलाइन बेटिंग व गेमिंग प्लेटफॉर्म लोटस365 और टेलीग्राम के माध्यम से हुए लेन-देन की भी जांच की जा रही है। मामले में 20 वर्षीय दिल्ली निवासी युवक और मूल रूप से बिलासपुर निवासी 26 वर्षीय युवक को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

पुलिस उनके मोबाइल फोन की तकनीकी जांच कर रही है। कुल्लू पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, ओटीपी या यूपीआई संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं।

विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट में करियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल तथा इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 'ग्रीन दिवाली' विषय पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर इको क्लब की प्रभारी सहायक आचार्य भूवि शर्मा ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा इनके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से मिट्टी के दीयों का प्रयोग करने, प्लास्टिक से बचने और प्राकृतिक सजावटी वस्तुएं अपनाने का आग्रह किया। करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के प्रभारी सहायक आचार्य अक्षय कुमार ने कहा कि त्योहार मनाते समय पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखना जरूरी है।

मंजू को मिली नगरोटा कॉलेज केंद्रीय छात्र संघ की कमान



भारेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महाविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (सीएससीए) का गठन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार सोनी ने नवमनोनीत पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि केंद्रीय छात्र संघ सलाहकार समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ संविधान, 2016 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों का मनोनयन शैक्षणिक मेरिट के आधार पर किया गया है। इसके तहत मंजू (एमएससी गणित) को अध्यक्ष, कोमल चौधरी (एमकॉम) को उपाध्यक्ष, श्रेया अग्निहोत्री (बीए प्रथम सेमेस्टर) को महासचिव तथा मानवी गुलेरिया (बीबीए प्रथम सेमेस्टर) को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं, समितियों और सोसायटियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुल 24 विद्यार्थियों को कक्षा प्रतिनिधि एवं विभिन्न गतिविधियों के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है।

इनमें एनसीसी, रोवर एवं रेंजर, एनएसएस, साइंस सोसायटी, कल्चरल सोसायटी, स्पोर्ट्स, इको क्लब, रेड रिबन क्लब, सोशल साइंस सोसायटी, भाषाई सोसायटी, सड़क सुरक्षा क्लब और कॉमर्स सोसायटी शामिल हैं। प्राचार्य ने कहा कि केंद्रीय छात्र संघ विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संगठनात्मक कौशल और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी समस्याओं और सुझावों को महाविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। शपथ समारोह के बाद प्राचार्य ने सभी नवमनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनसे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रो. संजय शर्मा, प्रो. सलिल सागर, प्रो. मंजीत सिंह, डॉ. कुंदन शर्मा, डॉ. माधवी पराशर, डॉ. राजीव कुमार, प्रो. सुनीता, प्रो. पूनम शर्मा सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

लाहौल-स्पीति में नवंबर माह के दौरान होंगे विभिन्न राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। जिला लाहौल-स्पीति में नवंबर माह के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से विभिन्न राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण संचालित किए जाएंगे।



भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में यह सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। सहायक निदेशक एवं प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय मंडी अमित कुमार ने बताया कि इन सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए जाने वाले आंकड़े देश और राज्यों में विकास योजनाओं, नीतियों तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में जिले के लपशक (लाहौल) क्षेत्र में वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण तथा कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के तहत खीनंग (लाहौल) क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। अमित कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ये कर्मचारी सुरक्षित डिजिटल उपकरणों और वेब पोर्टल के माध्यम से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त होने वाली सभी जानकारियों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इन आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा तथा किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एकत्रित आंकड़े देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का आकलन करने के साथ भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जिले के सभी चयनित परिवारों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों से अपील की है कि सर्वेक्षण के लिए पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करने और बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

ड्यूटी के साथ जनसेवा का जज्बा सड़क के गड्ढे भरकर होमगार्ड जवान यशपाल पेश कर रहे मिसाल



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड विभाग के जवान यशपाल अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ जनसेवा के जज्बे से भी लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वे ड्यूटी निभाने के साथ-साथ सड़क पर दिखाई देने वाले गड्ढों को स्वयं भरकर लोगों की राह आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यशपाल जब भी ड्यूटी के दौरान सड़क पर कोई गड्ढा या खराब हिस्सा देखते हैं, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसे ठीक करने में जुट जाते हैं। उनका यह प्रयास सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने और वाहन चालकों व राहगीरों को राहत पहुंचाने की दिशा में सराहनीय है। आमतौर पर लोग ऐसी समस्याओं को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यशपाल अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर जनहित में योगदान दे रहे हैं। स्थानीय लोग भी उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। उनकी यह पहल संदेश देती है कि समाज सेवा के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता की जरूरत होती है।

नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर का 48 .30 लाख का मकान सील



भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी से अर्जित करीब 48.30 लाख की संपत्ति का खाली कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त कर मकान सील कर दिया।

पुलिस के अनुसार PIT-NDPS एक्ट के तहत जब्त संपत्ति का वास्तविक और खाली कब्जा प्राप्त करने की यह हिमाचल प्रदेश में पहली कार्रवाई है। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई डमटाल निवासी शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह के विरुद्ध की गई है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली के आदेशानुसार आरोपी की कुल 48,30,997 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें गांव छन्नी, तहसील इंदौरा स्थित दो मंजिला आवासीय भवन, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, जिसकी कीमत 45,90,557 रुपए आंकी गई है। इसके अतिरिक्त नशे के कारोबार से अर्जित 2,40,440 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-के तहत जारी आदेश की अनुपालना में 4 नवंबर को पुलिस थाना डमटाल की टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मकान का निरीक्षण किया। इसके बाद बिना किसी विरोध या बल प्रयोग के मकान का खाली कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त किया गया। पुलिस ने मकान के मुख्य द्वार सहित अन्य प्रवेश द्वारों पर ताले लगाकर सील कर दिया तथा सरकारी जब्त संपत्ति का सूचना बोर्ड भी लगाया। एएसपी ने कहा कि नूरपुर पुलिस का अभियान केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर उनके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना भी प्राथमिकता है।

दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए सिर्फ दो घंटे की मोहलत

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। दीपावली पर्व के दौरान पटाखे चलाने के लिए जिला प्रशासन ने रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। जिला दंडाधिकारी किरण भड़ाना ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से 9 नवंबर तक लागू रहेंगे।

आदेशों के अनुसार 8 नवंबर को दीपावली के दिन निर्धारित दो घंटे की अवधि में ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। 125 डेसीबल अथवा 145 डेसीबल पीके से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने की अनुमति नहीं होगी।

अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में आने वाले शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और आग लगने की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर भी आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा।

पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान निर्धारित

अनंत ज्ञान, बिलासपुर। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बिलासपुर शहर में पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान निर्धारित किए हैं। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) सदर राज कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहर में पटाखों की बिक्री बास्केटबॉल मैदान, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर के सामने तथा नगर परिषद कार्यालय बिलासपुर के ग्राउंड परिसर में की जा सकेगी। प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर ही दुकानें लगाने की व्यवस्था की है, ताकि शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनी रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 और सहायिकाओं के 7 पदों के लिए साक्षात्कार 12 नवंबर को

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय इंदौरा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 11 रिक्त पदों को भरने के लिए 12 नवंबर, 2026 को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।

कार्यकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीत कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 पद डगाला-2, तडयां चमारां, बसंतपुर-2 और मझवाह-2 केंद्रों में भरे जाएंगे। वहीं, सहायिकाओं के 7 पद चलोह, ठठोली, सूरजपुर झिकला-2, कोठी, मंगवाल-3, भनूड़ी-1 और भलाख-1 आंगनवाड़ी केंद्रों में भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी पदों के लिए साक्षात्कार उपमंडल अधिकारी (ना.) इंदौरा के कार्यालय में आयोजित होंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित तिथि को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत व मानसिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें युवा: भड़ाना

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत, समर्पण और मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। किरण भड़ाना आज राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में माई युवा भारत के सौजन्य से आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग-2026 में बतौर मुख्यातिथि बोल रही थी।



उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। व्यक्ति की वास्तविक क्षमता इस बात से निर्धारित होती है कि वह असफलताओं का सामना किस प्रकार करता है और उनसे उबरकर दोबारा मेहनत करने के लिए कितना तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, निरंतर प्रयास व आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है।

उपायुक्त ने उपस्थित युवाओं को अपने साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपनी शिक्षा, करियर और जीवन की चुनौतियों से जुड़े प्रश्नों के लिए कभी भी उनके कार्यालय आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन के माध

खूबसूरत एथलीट एंड्रिया वर्गास

एंड्रिया वर्गास कोस्टा रिका की प्रसिद्ध एथलीट हैं, जो 100 मीटर बाधा दौड़ में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में कोस्टा रिका का प्रतिनिधित्व किया है।



स्पोर्ट्स विंडो

डब्ल्यूटीए टूर में माया और वैष्णवी ने हासिल की अपनी पहली जीत

एजेंसी, चेन्नई। भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन रेवती और वैष्णवी अडकर ने मंगलवार को यहां चेन्नई ओपन में उलटफेर करके पहली बार डब्ल्यूटीए टूर में जीत हासिल की। माया ने जहां तीन सेट के मुकाबले में विश्व में 115वें नंबर की खिलाड़ी और यहां आठवीं वरीयता प्राप्त कटारजीना कावा को उलटफेर का शिकार बनाया, वहीं वैष्णवी ने निर्णायक सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके ब्रिटेन की जोडी बुरेज को 3-6 6-3 7-5 से हराया। विश्व में 669वीं रैंकिंग की खिलाड़ी माया भी निर्णायक सेट में 2-5 से पीछे थी, लेकिन वह आखिर में पोलैंड की खिलाड़ी को दो घंटे और 27 मिनट में 6-4 2-6 7-6(5) से हराने में सफल रही।

एशियाई पैरा खेलों के पदक विजेताओं से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में हाल ही में हुए पैरा एशियाई खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से बृहस्पतिवार को मिलेंगे । मोदी यहां इंदिरा गांधी खेल परिसर में शाम 4 . 30 बजे भारतीय दल से मिलेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार,'प्रधानमंत्री इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे।' इस मौके पर पैरा कोच, भारतीय पैरालम्पिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी , राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद होंगे। भारत ने जापान के आइची नागोया में हुए पैरा एशियाई खेलों में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य समेत 114 पदक जीते।जापान के आइची-नागोया में पिछले महीने आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। भारत के कुल 97 पैरा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 114 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। यह एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।



यामल चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले युवा खिलाड़ी बने

एजेंसी, बार्सिलोना। बार्सिलोना के युवा फुटबॉलर लामिन यामल ने यूईएफए चैंपियंस लीग में ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। एस्टन विला के खिलाफ मंगलवार रात खेले गए मुकाबले में गोल दागते ही यामल इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले किशोर खिलाड़ी (20 वर्ष से कम) बन गए। उन्होंने फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर किलियन एमबाप्पे का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। 19 वर्षीय यामल ने कैंप नोउ में खेले गए मुकाबले के सातवें मिनट में एस्टन विला के खिलाफ शानदार गोल किया। चैंपियंस लीग में यह उनका 14वां गोल था। इससे पहले यह रिकॉर्ड एमबाप्पे के नाम था, जिन्होंने किशोर खिलाड़ी रहते हुए प्रतियोगिता में 13 गोल किए थे। इस मुकाबले में बार्सिलोना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एस्टन विला को 3-0 से हराया। दूसरे हाफ में राफिन्हा ने दो गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित की। बार्सिलोना वेबसाइट के मुताबिक लामिन यामल लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। मंगलवार को एस्टन विला के खिलाफ यह फॉरवर्ड खिलाड़ी 20 साल से कम उम्र में चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया। उनके नाम अब 14 गोल हो गए हैं। उन्होंने किलियन एमबाप्पे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी किशोरावस्था के दौरान 13 गोल किए थे।



बांग्लादेश ने महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए टीम का किया ऐलान

एजेंसी, नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाली आगामी आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 10 टीमों के इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की कमान नाहिदा अख्तर के हाथों में होगी। पिछले महीने उन्हें निगार सुल्ताना जोटी की जगह टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया था। कप्तान बनने के बाद नाहिदा के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा, जिसमें उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। बांग्लादेश को ग्रुप-बी में पाकिस्तान, थाईलैंड, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ रखा गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 12 नवंबर से होगी और फाइनल 25 नवंबर को होगा। अनुभवी बल्लेबाज सोभाना मोस्तारी को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। वहीं, पूर्व कप्तान निगार सुल्ताना जोटी भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं और खिलाड़ी के रूप में अपना योगदान जारी रखेंगी। आईसीसी वेबसाइट के अनुसार टीम की प्रमुख तेज गेंदबाज मारुफा अख्तर टखने की चोट के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। उनकी जगह तेज गेंदबाज दिशा बिस्वास को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज साथी रानी और ऑलराउंडर जन्नतुल फिरदुस सुमोना की टीम में वापसी हुई है।

'खेलो इंडिया' की तर्ज पर होगी 'खेलो हिमाचल' प्रतियोगिता

सीएम सुक्खू धर्मशाला में 20 नवंबर को करेंगे शुभारंभ; खर्च होंगे 22.5 करोड़ रुपए, खिलाड़ियों के होंगे डोप टेस्ट

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए प्रदेश सरकार एक नई पहल करने जा रही है। केंद्र सरकार के 'खेलो इंडिया' की तर्ज पर हिमाचल में 'खेलो हिमाचल' प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ 20 नवंबर को धर्मशाला में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इसका विधिवत आगाज करेंगे। इस आयोजन पर करीब 22.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है।



युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा आयोजन स्थल का निरीक्षण करते हुए।

युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खेल विभाग ने 'खेलो हिमाचल' आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रतियोगिता में पहले तीन खेल शामिल किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इनकी संख्या बढ़ाकर छह की जाएगी। खेलों के नाम जल्द फाइनल किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं ब्लॉक, सब-डिवीजन, जोनल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगी। इसके लिए खेल विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल टीम पंजीकरण में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग निर्धारित किया गया है।

ड्रोन-लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे

खेल मंत्री गोमा ने कहा कि प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर विजेता खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि रखी जाएगी। आयोजन को भव्य बनाने के लिए उद्घाटन समारोह में ड्रोन शो, लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें जिला स्तर पर चयनित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ एक स्टार कलाकार को भी बुलाने की योजना है। इसके लिए तीन से चार इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों ने प्रस्तुतियां दी हैं। बेहतर प्रस्तुति देने वाली कंपनी को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस आयोजन के लिए करीब 16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन पुरस्कार राशि और उद्घाटन समारोह का स्तर बढ़ने के चलते अब करीब 22.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रतियोगिता को चार से छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। मौजूदा योजना के अनुसार फरवरी के अंत या मार्च में इसका समापन किया जा सकता है।

नशे का सेवन करने वाले प्लेयर्स पर रहेगी नजर

खेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की निगरानी के लिए संबंधित जिला खेल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। खिलाड़ियों के डोप टेस्ट भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खेलों का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखारना है और इसमें किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहले वनडे में विराट कोहली ने बनाए 74 रन, अर्शदीप सिंह ने झटके 4 विकेट

भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया

एजेंसी, ऑकलैंड

भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अर्शदीप सिंह के 4 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई। गुरनूर बरार ने भी 3 विकेट लिए।

बारिश के कारण भारत को 32 ओवर में 143 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला। टीम ने 22.4 ओवर में 5 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 1 छक्का लगाया। यह विदेशी धरती पर वनडे में उनका दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। कोहली ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 34 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इस तरह ऑकलैंड में खेली गई पारी के दौरान कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वह कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। उनके इस अर्धशतक ने भारत के लक्ष्य का पीछा करने की राह आसान की। कप्तान शुभमन गिल ने 56 गेंदों पर 37 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में महज 22 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाले।



विराट ने चेज करने में सचिन को पीछे छोड़ा

कोहली ने इस मैच में वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। कई बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी अपने नाम कीं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की। कोहली के नाम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 1971 रन हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी की है। इसके अलावा शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी ने भी एक खास रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली की ये उपलब्धियों उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को दर्शाती हैं।

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज

एजेंसी, मेलबर्न

आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन को पीछे छोड़ा। केपटाउन टेस्ट में 9 विकेट लेने से पहले स्टार्क दूसरे नंबर पर थे। व्हाइट-बॉल क्रिकेट की रैंकिंग में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। भारत के श्रेयस अय्यर टी-20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने भी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में सुधार किया है। स्टार्क ने पहली बार अगस्त में टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया था। तब उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा था। हालांकि, इसके बाद साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन ने उनकी जगह ले ली थी। यानसन ने गकेबरहा टेस्ट में 6 विकेट लेकर पहला स्थान हासिल किया था। हालांकि केपटाउन में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा। इसके बाद स्टार्क फिर से शीर्ष पर पहुंच गए।



ऑलराउंडर रैंकिंग में यानसन टॉप पर

साउथ अफ्रीका के यानसन टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉपर पर बने हुए हैं। उन्होंने तीसरे टेस्ट में अर्धशतक लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की। वियान मुल्डर इस कैटेगरी में तीसरे और हार्मर पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स से मांगी कोचिंग की जिम्मेदारी

एजेंसी, चेन्नई

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ से जुड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने फ्रेंचाइजी से कोचिंग में जगह देने की मांग भी की है। हालांकि, अब तक उन्हें इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स में पूर्व साथी रहे रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा- 'मैंने अपनी इच्छा बता दी है और अब फैसला चेन्नई सुपर किंग्स को करना है। मेरे लिए सबसे अहम बात चेन्नई के साथ रहना और टीम को ट्रॉफी जिताने में मदद करना है।' रैना ने कहा - 'मैं सीएसके के साथ किसी भी भूमिका में काम करना पसंद करूंगा। उन्होंने आगे कहा- 'मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल और वर्ल्ड कप खेले हैं। सीएसके के लिए काफी रन बनाए। कई फाइनल खेले, कुछ जीते और कुछ हारे। दबाव में मानसिक रूप से अपना बेस्ट देना सीखा। मैं अपना अनुभव खिलाड़ियों के साथ साझा करना चाहता हूं।'



रैना ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए

रैना को उनके आईपीएल प्रदर्शन के कारण 'मिस्टर आईपीएल' के नाम से जाना जाता है। संन्यास के बाद वे क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। रैना 2008 के 2021 तक सीएसके से जुड़े रहे। बीच में जब सीएसके 2 साल के लिए सस्पेंड थी, तब 2016 और 2017 के सीजन में उन्होंने नई टीम गुजरात लायंस की कप्तानी की थी। रैना ने धोनी की कप्तानी में आईपीएल में 4 खिताब और 2 चैंपियंस लीग खिताब जीते। वे सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स में हासिल की पहली जीत

एजेंसी, पेरिस। रिकॉर्ड सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में खराब शुरुआत से उबरकर जीत हासिल की। पुरुषों के रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच ने पहले दौर में वैलेंटीन वैचेरोट को 6-7 (5), 7-5, 6-1 से हराया। जोकोविच ने अपने करियर का 103वां खिताब जीतकर रोजर फेडरर की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्ड जिमी कॉनर्स के नाम है जिन्होंने 109 खिताब जीते हैं। तीसरी वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन ने कैमरन नॉरी को 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया जबकि 11वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने बेंजामिन बोंजी पर 3-6, 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। अन्य मैचों में फ्रांस के मोइज़ कौमे को नूनो बोर्गेस से 6-3, 6-1 से और 2022 के चैंपियन होल्गर रूने को 12वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल से 7-5, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा।

वर्ल्ड टूर फाइनल्स खेलेंगी सिंधु

भारतीय खिलाड़ी ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए किया क्वालिफाई

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह टूर्नामेंट 9 से 13 दिसंबर तक चीन के होंगझोउ में खेला जाएगा। सिंधु 2021 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। वे 2021 में इसकी उपविजेता रही थीं। 2022 में भी सिंधु ने क्वालिफाई किया था, लेकिन बाएं टखने में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण नाम वापस लेना पड़ा। इसके बाद वे 2023 से 2025 तक इस टूर्नामेंट में नहीं खेलीं।

विमेंस सिंगल्स में 8 खिलाड़ियों को जगह मिलती है। इनमें से सिंधु समेत 5 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुकी हैं। साउथ कोरिया की एन से-युंग, जापान की अकाने यामागुची और चीन की वांग झी यी और चेन यू फेई ने भी जगह पक्की कर ली है। बाकी 3 स्थानों के लिए 6 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है। सिंधु ने 2026 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जुलाई में जापान ओपन का खिताब जीता। 19 जुलाई को खेले गए फाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। इसके बाद अक्टूबर में वे फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचीं। हालांकि, खिताबी मुकाबले में उन्हें एन से-युंग के खिलाफ 21-16, 11-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा।



बीडब्ल्यूएफ के 25 सेकंड शॉट क्लॉक को लेकर चिंता जताई

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू ने बुधवार को कहा कि बैडमिंटन विश्व महासंघ की 25 सेकंड 'शॉट क्लॉक' पहल की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि उन्होंने और कई अन्य खिलाड़ियों ने इसकी निष्पक्षता को लेकर विश्व ईकाई से शिकायत की है। 'शॉट क्लॉक' को इस साल बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर के चुनिंदा टूर्नामेंटों में प्रायोगिक आधार पर इस्तेमाल किया गया । इसके तहत खिलाड़ी को एक रेली खत्म होने के बाद सर्विस के लिये तैयार होने के लिये 25 सेकंड का समय दिया जाता है। सिंधू ने एक वर्चुअल बातचीत में कहा ,'काफी उतार चढाव देखे गए हैं। कुछ लोगों के लिये यह अभी भी नया है और कई बार कुछ अंपायर काफी सख्त होते हैं।'

लोकतंत्र में धरना-भूख हड़ताल की जगह नहीं : केरल हाईकोर्ट

यूनिवर्सिटी राजनीति नहीं पढ़ाई की जगह, आंदोलनकारी छात्रों को संस्थान से निकालने की इजाजत

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों की संवैधानिक लोकतंत्र में जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा- शिक्षण संस्थान पढ़ाई के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्रों को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कालडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 निलंबित छात्रों के मामले में की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब 16 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े इन छात्रों ने परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे उनका पूरा सेमेस्टर बर्बाद हो सकता है।



एसएफआई के प्रदर्शन में वाइस चांसलर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करने का आरोप

यूनिवर्सिटी में 13 अगस्त को सिंडिकेट की बैठक के दौरान एसएफआई से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया था। वे कैंपस में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पानी की समस्या और शिक्षकों के खाली पद भरने जैसी 18 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक किया। इसमें प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार दिखाया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे वाइस चांसलर सीजा थॉमस का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार बताया। वाइस चांसलर ने आरोप लगाया कि सिंडिकेट बैठक के बाद कैंपस से निकलते समय 18 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोका और धक्का दिया। उन्होंने बाल खींचने और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। घटना के बाद पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और चार एसएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

सेंसेक्स में 302 और निफ्टी में 101 प्वाइंट्स का उछाल

एजेंसी, मुंबई

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछलकर 77,219.65 पर पहुंचा। निफ्टी भी 23,900 के स्तर को पार कर 23,911.70 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 301.80 अंकों (0.39 फीसदी) की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी में 100.86 अंकों (0.42 फीसदी) का लाभ हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 0.75 फीसदी तक उछले।

सोना 3,486 चांदी 7,775 रुपए महंगी

नई दिल्ली। धनतेरस से पहले 4 नवंबर को सोने-चांदी के दाम में बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,486 रुपए बढ़कर 1.41 लाख रुपए पर पहुंच गया है। एक किलो चांदी 7,775 रुपए महंगी होकर 1.84 लाख रुपए पर पहुंच गई है। धनतेरस 6 नवंबर को मनाई जाएगी।

कैनवा 1271 कर्मचारियों को बाहर निकालेगी, 22% स्टाफ पर असर

एजेंसी, नई दिल्ली

ऑनलाइन डिजाइन और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म कैनवा ने अपने वर्कफोर्स में 22% से ज्यादा की कटौती का ऐलान किया है। कंपनी के इस फैसले से कम से कम 1,271 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, उनका रोल बदलेगा या फिर उन्हें सेंट्रल हब्स में रिलोकेट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया की इस जानी-मानी टेक कंपनी में यह बड़ा बदलाव हो रहा है। कैनवा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों को भेजे एक नोट में बताया कि सिडनी स्थित इस कंपनी की ग्रोथ एक दशक में पहली बार सुस्त हुई है।

उन्होंने इस रीऑर्गनाइजेशन को कंपनी के 13 साल के इतिहास का सबसे कठिन समय बताया है। पर्किन्स ने लिखा कि नई टेक्नोलॉजी लोगों के क्रिएट करने के तरीके और उनकी उम्मीदों को बदल रही है। मैं इस कठिन फैसलों पर पहुंची हूं कि छोटे बदलाव काफी नहीं होंगे।

स्टेटस सिंबल ज्यादा बच्चे अमीरों के लिए रुतबे की निशानी, परवरिश पर करोड़ों रुपए खर्च

अमेरिका में बढ़ा तीन बच्चे पैदा करने का चलन

एजेंसी, वॉशिंगटन

अमेरिका के अमीर परिवारों में ज्यादा बच्चे पैदा करने का चलन बढ़ गया है। इनके लिए यह रुतबे की निशानी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सबसे अमीर 1% परिवारों में से करीब आधे परिवारों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। वहीं, कम कमाई समूह में तीन बच्चे वाले परिवार करीब 40 से 43% हैं।

अमेरिका में एक परिवार एक बच्चे की परवरिश पर 18 साल तक करोड़ों रुपए खर्च करता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी रकम चुका पाना महंगाई के इस दौर में लगभग नामुमकिन है।

अमीरों में 1990 से शुरू हुआ ज्यादा बच्चों का चलन

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में ज्यादा बच्चे का चलन 1990 के दशक से चला आ रहा है। अर्थशास्त्री माइक कॉन्जल का कहना है कि अमीर परिवारों के लिए तीसरा बच्चा स्टेटस सिंबल यानी रुतबे की निशानी बन गया है। उनके मुताबिक, महंगाई और बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च आम परिवारों को कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन इसका असर सबसे अमीर 1% परिवारों पर उतना नहीं पड़ता। मिडिल क्लास परिवारों को अपनी कमाई में घर का किराया, बिल, बचत और बच्चों की जरूरतों के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है। तीसरा बच्चा होने पर इन खर्चों का बोझ और बढ़ जाता है।



बच्चों पर हर वर्ष खर्च करने पड़ते हैं 15 लाख रुपए

अमेरिकी कंपनी लेंडिंगट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक बच्चे को जन्म से 18 साल की उम्र तक पालने में औसतन 3 करोड़ खर्च होते हैं। इस हिसाब से हर साल करीब 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसमें बच्चे के खाने, घर, आने-जाने, स्वास्थ्य बीमा और देखभाल जैसे खर्च शामिल हैं। हालांकि, यह औसत अनुमान है। हर परिवार का खर्च उसकी कमाई, रहने की जगह और बच्चों की जरूरतों के हिसाब से अलग हो सकता है।